वर्ष 12 • अंक 268 • 12 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

शनिवार 28 दिसंबर 2019

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 4

रेलवे की कमजोर माली हालत से चिंता

दिलीप सांघवी ▸▸ पृष्ठ 2

सुजलॉन हुई दिवालिया तो सांघवी को नुकसान

डॉलर रु. 71.40 ▲ 10 पैसे | यूरो रु. 79.40 ▲ 40 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 38788 ▲ 152 रुपये | सेंसेक्स 41575.10 ▲ 411.40 | निफ्टी 12245.80 ▲ 119.30 | निफ्टी फ्यूचर्स 12319.30 ▲ 73.50 | ब्रेंट क्रूड 67.50 डॉलर ▼ 0.10 डॉलर

एक नज़र

बैंक प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री की बैठक आज

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरकारी बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन तथा उनके कारोबार की वृद्धि की समीक्षा करने के लिए इन बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्याधिकारियों के साथ शनिवार को बैठक करेंगी। सूत्रों ने बताया कि मांग और उपभोग को तेज करने में बैंकों की भूमिका को देखते हुए बजट से पहले सरकारी बैंकों के सीईओ और प्रबंध निदेशकों के साथ वित्त मंत्री की यह बैठक विशेष महत्त्व रखती है। सीतारमण 1 फरवरी को अपना दूसरा पूर्ण बजट पेश कर सकती हैं।

निवेश सलाहकार करें ग्राहक जोखिम का आकलन

निवेश सलाहकारों के संचालन को और सुदृढ़ बनाने के मसकद से बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने उनसे ग्राहकों के जोखिम का समुचित आकलन करने और ऐसे निवेशकों को किसी भी तरह की सलाह देने से पहले उनकी सहमति लेने को कहा है। नियामक ने निवेश सलाहकारों को किसी भी उत्पाद और सेवाओं के लिए मुफ्त में प्रायोगिक सलाह मुहैया कराने से भी मना किया है। नए नियम 1 जनवरी, 2020 से प्रभावी होंगे।

आंशिक पेंशन निकासी सुविधा 1 जनवरी से

श्रम मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन कोष से एकमुश्त आंशिक निकासी यानी कम्युटेशन की सुविधा 1 जनवरी से देगा। इस कदम से 6.3 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इन पेंशनभोगियों ने अपनी पेंशन निकासी का विकल्प चुना था और 2009 से पहले सेवानिवृत्ति के समय उन्हें पेंशन मद में जमा राशि में से कुछ हिस्सा एकमुश्त निकालने की अनुमति मिल गई थी। ईपीएफओ ने 2009 में पेंशन मद में से निकासी के प्रावधान को वापस ले लिया था। इस सुविधा के तहत पेंशनधारक को अग्रिम में पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त दे दिया जाता है। उसके बाद अगले 15 साल के लिए उसकी मासिक पेंशन में एक तिहाई की कटौती की जाती है।

125 करोड़ लोगों के पास है आधार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने शुक्रवार को कहा कि देश के 125 करोड़ लोगों को आधार जारी किया जा चुका है। प्राधिकरण ने एक बयान में इस उपलब्धि की जानकारी दी। उसने कहा कि देश के प्रमुख पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का चलन बढ़ रहा है। अब तक आधार आधारित सत्यापन सेवाओं का 37,000 करोड़ बार इस्तेमाल हो चुका है। प्राधिकरण को रोजाना सत्यापन के करीब 3 करोड़ अनुरोध मिलते हैं। साथ ही उसे रोज आधार अपडेट के तीन-चार लाख अनुरोध मिलते हैं।

कजाकस्तान विमान हादसे में 12 की मौत, कई घायल

कजाकस्तान के अल्माटी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद 100 यात्रियों को लेकर जा रहा एक विमान शुक्रवार को एक मकान से टकरा गया। इस हादसे में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई जबकि दर्जनों घायल हो गए। देश की आपात समिति द्वारा जारी एक वीडियो में किफायती विमानन सेवा कंपनी बेक एयर का विमान कई टुकड़ों में टूटा हुआ नजर आ रहा है। विमान में 95 यात्री और चालक दल के पांच सदस्य सवार थे।

व्यापार गोष्ठी

कारोबार के लिहाज से कैसा रहा साल 2019?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड , नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201
या फिर ई-मेल करें goshthi@bsmail.in
अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या बैंकों को एनपीए में कमी लाने के लिए करने चाहिए सख्त उपाय

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या एलआईसी को रिटर्न बढ़ाने के लिए इक्विटी पर लगाना चाहिए दांव? हां **36.36%** नहीं **63.64%**

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट में कहा

एनपीए बढ़ा मगर बैंक ज्यादा सुदृढ़

अनूप रॉय
मुंबई, 27 दिसंबर

मार्च 2019 में सकल गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) का अनुपात सात साल में पहली बार घटने के बाद एक बार फिर भारतीय बैंकों का सकल एनपीए अनुपात बढ़ने की आशंका है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा आज जारी छमाही वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में नरमी और उधारी मांग घटने से कुल लोन बुक में फंसे कर्ज की हिस्सेदारी बढ़ गई है।

हालांकि सरकार द्वारा बैंकों में पूंजी डालने और आरबीआई की ओर कई कदम उठाए जाने से बैंकिंग प्रणाली इस साल जून की तुलना में बेहतर स्थिति में है। इससे पहले वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट जून में जारी किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है, 'सितंबर 2019 में बैंकों का सकल एनपीए अनुपात 9.3 फीसदी था जो सितंबर 2020 में 9.9 फीसदी हो सकता है। वृहद आर्थिक परिस्थितियां, चूक के मामले बढ़ने और उधारी वृद्धि कम रहने से सकल एनपीए के बढ़ने का खतरा है।'

रिपोर्ट को वित्तीय स्थायित्व एवं विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति ने तैयार किया है, जिसे आरबीआई द्वारा जारी किया गया। इस हफ्ते की शुरुआत में आरबीआई ने ज्ञान एवं प्रगति रिपोर्ट में कहा था कि बैंकिंग क्षेत्र में आगे सुधार वृहद आर्थिक परिदृश्य में बदलाव पर निर्भर करेगा।'

रिपोर्ट में कहा गया है कि भू-राजनीतिक अनिश्चितता का जोखिम पूरे वित्तीय तंत्र पर बना हुआ है। निर्यात पर दबाव रह सकता है लेकिन चालू खाते का घाटा नियंत्रण में रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार, खपत और निवेश में कमी वैश्विक वित्तीय बाजारों के लिए अहम चुनौती बनी रह सकती है। 2019-20 की दूसरी तिमाही में सकल मांग में कमी आई थी जिससे आगे भी वृद्धि पर असर पड़ सकता है।

आगे के परिदृश्य पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिपोर्ट में कहा है कि मौद्रिक नीति का लाभ वास्तविक अर्थव्यवस्था को मिलना सुनिश्चित होना चाहिए न कि वित्तीय बाजार की मजबूती में इसका उपयोग हो।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई ने आर्थिक माहौल के हिसाब से प्रतिक्रिया दी है और सक्रिय मौद्रिक नीति प्रदान करने का प्रयास किया है। दास ने संपूर्ण बोर्ड स्तर पर कारोबारी संचालन को बेहतर बनाने के महत्त्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह एक अहम कारक है जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी ताकत के साथ ऊपर उठाने की क्षमता है।

बैंकिंग क्षेत्र में स्थायित्व के संकेत दिख रहे हैं, वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपने प्रदर्शन में सुधार लाना चाहिए और परिचालन जोखिम से होने वाले नुकसान के लिए समुचित उपाय करने चाहिए। दास ने कहा कि निजी क्षेत्र के बैंकों को भी कारोबारी संचालन के पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। **(शेष पृष्ठ 3 पर)**

■ **संबंधित खबर : पृष्ठ 3**

- **बैंकों का एनपीए सितंबर 2020 तक बढ़कर 9.9 फीसदी होने की आशंका**
- **पुनर्पूंजीकरण से बैंकिंग तंत्र में आया है सुधार**
- **खपत और निवेश में सुधार अहम चुनौती**
- **वाणिज्यिक क्षेत्र की ओर से उधारी मांग में सुधार लाने की जरूरत**
- **एनबीएफसी में व्यवस्थागत जोखिम में आई कमी**

अधिशेष हस्तांतरण पर गतिरोध बरकरार

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 27 दिसंबर

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अधिशेष के सरकारी खजाने में हस्तांतरण को लेकर बोर्ड और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध के जल्द खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं।

आम बजट से पहले अपने राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार की नजर सेबी के अधिशेष पर है। हाल में सरकार ने इस बारे में सेबी से यथास्थिति रिपोर्ट मांगी थी। सरकार नए नियमों के हिसाब से अधिशेष का हस्तांतरण चाहती है।

मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि वित्त मंत्रालय में संबंधित विभागों ने हाल में अधिशेष के बारे में सेबी से जानकारी मांगी थी ताकि सरकार अपनी आय और खर्च का हिसाबकिताब कर सके और उसके मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष के लिए राजस्व अनुमान और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमान लगाए जा सकें।

दूसरी ओर सेबी ने अब तक वित्त अधिनियम, 2019 के प्रावधान का पालन नहीं किया है जिसके मुताबिक उसे सालाना अधिशेष का आरक्षित कोष बनाना है और फिर अपने सामान्य कोष में से 75 फीसदी नकदी सरकारी खजाने में हस्तांतरित करनी है। सेबी को खुद से जुड़े कानून के तहत सारे खर्च निकालने के बाद शेष राशि सरकार को हस्तांतरित करनी है। सूत्रों के मुताबिक यह राशि इतनी अधिक नहीं होगी कि इससे सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पाट सके लेकिन सेबी की स्वायत्तता के लिए यह बेहद अहम है।

संशोधित कानून के मुताबिक सेबी अपने वार्षिक अधिशेष में से केवल 25 फीसदी राशि ही रख सकता है। यह राशि पिछले दो वर्षों के दौरान उसके कुल वार्षिक खर्च से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसे शेष राशि समेकित निधि में हस्तांतरित करनी होगी। अधिकारियों के मुताबिक 31 मार्च, 2018 तक सेबी का अधिशेष 3,606 करोड़ रुपये था। यानी सेबी को इस वित्त वर्ष में सरकार को 2,800 करोड़ रुपये देने पड़ सकते हैं। वित्त विधेयक के संसद के दोनों सदनों में पारित होने से सेबी कानून में स्वत: बदलाव हो गया। इस संशोधन में समीक्षा और पुनर्विचार का प्रावधान था जिसका सेबी ने विरोध किया है।

सूत्रों के मुताबिक इस फैसले के बाद सेबी ने आर्थिक मामलों के विभाग को कम से कम दो पत्र लिखे हैं। इनमें बाजार नियामक ने कहा कि यह प्रस्ताव सलाह मशविरे के बिना जल्दबाजी में किया गया है और इस तरह का कोई भी फैसला वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (एफएसडीसी) को लेना चाहिए। एफएसडीसी वित्तीय क्षेत्र का नियामक है। वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है और सेबी सहित वित्तीय क्षेत्र के सभी नियामक इसके सदस्य हैं।

सेबी का मानना है कि निवेशकों के हितों के संरक्षण में उसके अधिशेष की काफी अहमियत है। सेबी एम्पलॉयीज एसोसिएशन, ब्रोकर्स फोरम और बाजार के कई भागीदारों ने भी सरकार के इस कदम का विरोध किया है। उनका कहना है कि यह एक तरह से सेबी की स्वायत्ता में हस्तक्षेप है। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण और पेंशन फंड नियामक भी इस मामले में सेबी का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आशंका है कि आगे उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। इस बारे में सेबी को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं आया।

सेबी की एक दलील यह भी है कि नया प्रावधान अतिरिक्त कर की तरह है क्योंकि सेबी सेवाएं देने के लिए इंटरमीडियरी से फीस वसूलता है लेकिन अधिशेष हस्तांतरण बाजार के भागीदारों पर एक अतिरिक्त कर बन जाएगा।

- **राजकोषीय घाटा कम करना चाहती है सरकार**
- **उसकी नजर सेबी के अधिशेष पर**
- **अधिशेष के बारे में मांगी जानकारी**
- **सरकार के कदम का हो रहा है विरोध**

बहादुर की विदाई

फोटो: पीटीआई

भारतीय वायुसेना के प्रतिष्ठित लड़ाकू विमान मिग-27 को शुक्रवार को सेवा मुक्त कर दिया गया। जोधपुर एयर बेस पर सेवा मुक्त होने से पहले परवाज भरने की तैयारी करता मिग-27। 1999 के करगिल युद्ध में इन विमानों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।

आरबीआई और वैश्विक संकेतों से बाजार में तेजी

जश कृपलानी
मुंबई, 27 दिसंबर

बैंकिंग शेयरों की अगुआई में सेंसेक्स और निफ्टी आज करीब एक फीसदी बढ़त पर बंद हुए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दूसरे चरण के बॉन्ड की खरीद-बिक्री की घोषणा से बैंकों के शेयरों में तेजी देखी गई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा नियमों में ढील दिए जाने की उम्मीद से मिडकैप शेयर भी खासी बढ़त पर बंद हुए। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर सकारात्मक संकेतों का भी निवेशकों की धारणा पर असर पड़ा।

सेंसेक्स में ऐक्सिस बैंक में सबसे ज्यादा 3.3 फीसदी की तेजी आई। भारतीय स्टेट बैंक 2.2 फीसदी और आईसीआईसीआई बैंक 2 फीसदी बढ़त पर बंद हुआ। बीएसई बैंकेक्स 1.2 फीसदी तेजी पर बंद हुआ। 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों का प्रतिफल एक माह के निचले स्तर 6.1 फीसदी पर रहा।

सेंसेक्स 411.38 अंक चढ़कर 41,575.14 पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी 119.25 अंक की बढ़त के साथ 12,245.80 पर बंद हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 81 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 125 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप भी करीब 8 फीसदी ऊपर बंद हुआ। बाजार के सूत्रों के अनुसार मिडकैप शेयरों में तेजी सेबी द्वारा म्युचुअल फंडों की योजनाओं के लिए नियमों में बदलाव करने की चर्चा से आई है। बाजार के जानकारों का कहना है कि यह बाजार में व्यापक स्तर की तेजी के संकेत हैं।

भारतीय मनोरंजन उद्योग बन सकता है विकास का इंजन

वनिता कोहली-खांडेकर
नई दिल्ली, 27 दिसंबर

वर्ष 2010- माई नेम इज खान के निर्देशक करण जौहर और मुख्य अभिनेता शाहरुख खान जब आधी फिल्म बना चुके थे तो उन्हें लगा कि उन्हें एक ऐसे स्टूडियो की जरूरत है जो उनकी फिल्म को भारतीय दर्शकों से परे ले जा सके।

एक दशक में बदला परिदृश्य

यह अधिकांश भारतीय फिल्मों के लिए एक मुश्किल काम था। उन्होंने फॉक्स स्टार से संपर्क किया जिसने फिल्म को अपने हाथ में लिया और इसके पीछे अपनी पूरी ताकत झोंक दी। माई नेम इज खान 68 देशों में 1,400 सिनेमाघरों में रिलीज की गई और 65 देशों में इसे टीवी स्क्रीनों पर दिखाया गया। यह किसी भी भारतीय फिल्म के लिए नई बात थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस और टीवी अधिकारों से 10 करोड़ डॉलर से अधिक कमाई की और यह उस समय तक दुनिया में भारत की सबसे सफल फिल्म थी। क्या हमारी कहानियां देश की सीमाओं से बाहर निकल गई थीं?

वर्ष 2019- जुलाई 2018 में हिंदी शो सेक्रेड गेम्स की 190 देशों में नेटफ्लिक्स के 12.5 करोड़ ग्राहकों के लिए स्ट्रीमिंग शुरू हुई। द गार्डियन से लेकर द न्यूयॉर्क टाइम्स तक हर बड़े प्रकाशन समूह ने इसकी समीक्षा की। एक वर्ष बाद सितंबर 2019 में इसे लस्ट स्टोरीज (नेटफ्लिक्स) और द रीमिक्स इंडिया (एमेजॉन प्राइम वीडियो) के साथ इंटरनैशनल ऐमी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया। उसी महीने द फैमिली मैन का लॉस एंजिलिस में प्रीमियर हुआ और फिर इसे एमेजॉन प्राइम वीडियो पर 200 देशों में 7.5 करोड़ घरों में दिखाया गया। एमेजॉन प्राइम वीडियो अभी 12 भारतीय शो दिखा रही है और आगे 30 और शो आने वाले हैं। कंपनी के उपाध्यक्ष जय मरीन कहते हैं कि ये शो देखने वाले तीन दर्शकों में से एक भारत से बाहर का है। इस बीच सेक्रेड गेम्स ने द न्यूयॉर्क टाइम्स की इस दशक की 30 सर्वश्रेष्ठ इंटरनैशनल सीरीज में जगह बनाई है। **(शेष पृष्ठ 4 पर)**

बीते दशक में शीर्ष दस मीडिया फर्में

वित्त वर्ष 2010	(~ करोड़)	वित्त वर्ष 2019	(~ करोड़)
टाइम्स समूह	5,000	ज़ी समूह	16,495
ज़ी समूह	4,009	स्टार इंडिया	11,956
स्टार इंडिया	3,525	टाइम्स समूह	10,000
एयरटेल (मीडिया)	2,900	गूगल इंडिया	9,337
एचटी मीडिया	1,453	सोनी	6,309
सन नेटवर्क	1,395	टाटा स्काई	6,148
नेटवर्क18	1,275	नेटवर्क 18	5,068
सोनी	1,250	एयरटेल टीवी	4,100
डीबी कॉर्पोरेशन	1,074	सन नेटवर्क	3,782
जागरण प्रकाशन	942	पीवीआर सिनेमाज	3,118

नोट - गूगल इंडिया का राजस्व वित्त वर्ष 2018 का है।
स्रोत - सालाना रिपोर्ट, कंपनी पंजीयक और मीडिया पार्टनर्स एशिया

मीडिया मनोरंजन उद्योग का आकार

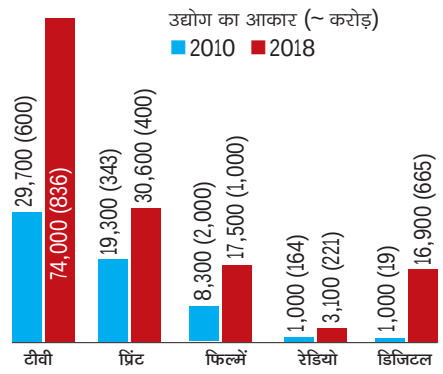

नोट - कोष्ठक में वैसे दर्शकों की संख्या दस लाख में दिखाई गई है, जो टिकट खरीद कर फिल्में देखते हैं। टीवी और ऑनलाइन दर्शक शामिल नहीं है। स्रोत : फिक्की -केपीएमजी और फिक्की-ईवाई रिपोर्ट, आईआरएस

संक्षेप में

सुंदरम-क्लेटॉन तीन दिन बंद रखेगी संयंत्र

दोपहिया व तिपहिया निर्माता टीवीएस मोटर की होल्डिंग कंपनी सुंदरम-क्लेटॉन ने 28, 30 और 31 दिसंबर 2019 को संयंत्रों में कामकाज बंद रखने का फैसला किया है। कंपनी ने कहा, विभिन्न क्षेत्रों में कारोबारी मंदी के कारण यह फैसला लिया गया है। कंपनी के विनिर्माण संयंत्र पाडी और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी चेन्नई, ओरागदम (चेन्नई के पास) और होसुर औद्योगिक केंद्र में है। इसके अलावा कंपनी का संयंत्र अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना में भी है। *बीएस*

आईआरएफसी ने जुटाए 1,580 करोड़ रुपये

इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (आईआरएफसी) ने शुक्रवार को बीएसई के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैकेनिज्म प्लेटफॉर्म पर निजी प्लेसमेंट के आधार पर बॉन्ड जारी करके 1,580 करोड़ रुपये जुटाए। एक्सचेंज ने एक बयान में कहा कि इसमें 790 करोड़ रुपये का ग्रीन शू विकल्प शामिल है। बीएसई बॉन्ड प्लेटफॉर्म पर कुल 1,720 करोड़ रुपये की 37 बोलियां मिलीं। बीएसई के मुख्य कार्याधिकारी एवं प्रबंध निदेशक आशीष कुमार चौहान ने कहा कि एक्सचेंज का मानना है कि भारतीय बॉन्ड बाजार में वृद्धि की पर्याप्त संभावना है और भारत अपनी घरेलू बचत का विवेकपूर्ण तरीके से समायोजन कर रहा है। आईएफआरसी के एमडी अमिताभ बनर्जी ने कहा, 'हम इस पूरी प्रक्रिया के निर्बाध पूरा होने के लिए बीएसई टीम सहित इसमें हिस्सा लेने वाले सभी भागीदारों का धन्यवाद करते हैं।' *एजेंसियां*

सांघवी भारी नुकसान के कगार पर

सुजलॉन एनर्जी के दिवालिया होने से दिलीप सांघवी को लगेगा तगड़ा झटका

देव चटर्जी
मुंबई, 27 दिसंबर

अक्षय ऊर्जा कंपनी सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड अगले सप्ताह दिवालिया अदालत का रुख कर सकती है। इससे सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज के अरबपति प्रवर्तक दिलीप सांघवी को भारी नुकसान हो सकता है। सांघवी ने 2014 में इस अक्षय ऊर्जा कंपनी में 1,400 करोड़ रुपये के अपने व्यक्तिगत निवेश से 23 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की थी। सुजलॉन के प्रवर्तक तांती परिवार के बाद सांघवी को संभवत: सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

बैंकरों ने कहा कि सुजलॉन ऋण पुनर्गठन के लिए दिसंबर के अंत तक की समय-सीमा पर खरी नहीं उतरी है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, लेनदारों ने सुजलॉन के ऋण पुनर्गठन के लिए एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अनुमोदन की मांग की थी लेकिन कंपनी उसे हासिल करने में विफल रही।

इस अक्षय ऊर्जा कंपनी के लेनदारों ने इसी साल जून में एक अंतर-ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद कंपनी ने एक ऋण पुनर्गठन योजना तैयार की जिसके तहत ऋण को दो श्रेणियों- स्थायी एवं अस्थायी- में बांटा गया था। हालांकि रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने लेनदारों को संकेत दिया कि कंपनी ऋण अदा करने में समर्थ नहीं होगी क्योंकि उसकी आय वित्तीय लागत की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

कैलेंडर वर्ष 2019 में शुक्रवार तक सुजलॉन एनर्जी के शेयर में 64 फीसदी की गिरावट आ चुकी है और उसकी हैसियत 1,053 करोड़ रुपये की है। इस प्रकार सांघवी की हिस्सेदारी का मूल्यांकन 242 करोड़ रुपये होता है। धनाढ्य व्यक्तियों की ब्लूमबर्ग की सूची में इस साल जनवरी में सांघवी 10वें पायदान पर मौजूद थे लेकिन करीब 1 अरब डॉलर के नुकसान के साथ उनकी कुल शुद्ध हैसियत 7.3 अरब डॉलर रह गई है। सन फार्मा के शेयर में महज 1 फीसदी की मामूली गिरावट के बावजूद सांघवी को तगड़ा झटका लगा।

एक बैंकिंग सूत्र ने कहा कि सुजलॉन को बिजली क्षेत्र की अन्य कंपनियों के साथ जनवरी के पहले सप्ताह तक ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता के प्रावधानों के तहत ऋण समाधान के लिए भेजा जाएगा। कंपनी पर भारतीय बैंकों के करीब 11,300 करोड़ रुपये के ऋण बोझ तले दबी है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के तहत बैंकों को मार्च तिमाही में इस ऋण के लिए प्रावधान करना होगा।

सुजलॉन ने इस बाबत जानकारी के लिए भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया। सांघवी के प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार किया।

वित्त वर्ष 2013 में बैंकों ने पवन ऊर्जा क्षेत्र में सकारात्मक दीर्घावधि परिदृश्य की उम्मीद में सुजलॉन के कॉरपोरेट ऋण पुनर्गठन (सीडीआर) की प्रक्रिया शुरू की थी ताकि कंपनी को लाभप्रदता की राह पर लौटने में मदद मिल सके।

सीडीआर पैकेज 28 मार्च 2013 को ऋण पुनर्गठन समझौते पर सभी बैंकों के हस्ताक्षर होने के बाद लागू हुआ। साल 2014 तक सांघवी एक निवेशक के तौर पर सामने आए और उन्होंने 450 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश का वादा किया। साल 2015 में सुजलॉन ने जर्मनी की अपनी सहायक इकाई सेनवियन एसए को 1 अरब यूरो में सेंटरब्रिज पार्टनर्स को बेच दिया और जुटाई गई रकम का इस्तेमाल ऋण पुनर्भुगतान में किया।

निवेश पर नुकसान

- अक्षय ऊर्जा कंपनी में सांघवी ने 2014 में 1,400 करोड़ रुपये के निवेश से ली थी 23 फीसदी हिस्सेदारी
- सुजलॉन के प्रवर्तक तांती परिवार के बाद सांघवी को होगा सबसे अधिक नुकसान
- बैंकरों ने कहा, ऋण पुनर्गठन के लिए दिसंबर के अंत तक की समय-सीमा पर खरी नहीं उतरी कंपनी

न्यूटैनिक्स की नजर सरकारी ठेकों पर

नेहा अलावधी
नई दिल्ली, 27 दिसंबर

तीन भारतीय सह-संस्थापकों वाली क्लाउड कंप्यूटिंग फर्म न्यूटैनिक्स भारत में सरकारी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। करीब तीन साल पहले नैसडैक में कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम को जबरदस्त सफलता मिली थी।

न्यूटैनिक्स के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (बिक्री- भारत एवं सार्क) बालकृष्णन अनंतरामन ने कहा कि कंपनी भारत में सरकारी ग्राहकों पर बड़ा दांव लगाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी को सरकार के राज्य एवं केंद्र और रक्षा क्षेत्रों में काफी अवसर दिख रहे हैं। न्यूटैनिक्स हाइपरकन्वर्ज्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर (एचसीआई) कारोबार में अग्रणी कंपनी है।

अनंतरामन ने कहा, 'इसका मतलब यह हुआ कि हम एक परिवेश में काम करते हैं और इसलिए हम अपने संसाधनों को लगा रहे हैं। वास्तव में हम स्मार्ट सिटी, राज्य के डेटा सेंटर के आधुनिकीकरण के लिए काम करते हैं और जाहिर तौर पर हम अन्य तमाम सरकारों की परियोजना पर काम करते हैं। इससे स्पष्ट है कि हम इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।' नेटवर्क वर्ल्ड के अनुसार, एचसीआई एक सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा है जो भंडारण, कंप्यूटिंग एवं नेटवर्किंग को एक प्रणाली के तहत एकीकृत करता है ताकि डेटा सेंटर की जटिलता को कम किया जा सके और उसकी क्षमता बढ़ाई जा सके।

जहां तक चैनल साझेदारों का सवाल है तो न्यूटैनिक्स ने टियर-1 चैनल साझेदारों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। अनंतरामन ने कहा, 'मैं समझता हूं कि पिछले तीन-चार वर्षों के दौरान हमारी वृद्धि को टियर-2 साझेदारों से रफ्तार मिली। अब हम बड़े साझेदारों के साथ काम कर रहे हैं जिनमें टाटा कंसल्टैंसी सर्विसेज (टीसीएस) और विप्रो जैसी कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा लार्सन ऐंड टुब्रो और कोटक जैसे ग्राहकों पर भी हमारी नजर है।'

भारत में कंपनी के ग्राहकों में स्टॉक एक्सचेंजों, ब्रोकरों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, वित्तीय सेवा एवं बीमा, आईटी और आईटी समर्थ सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनियां शामिल हैं।

टाटा मोटर्स का प्रकृति ई-मोबिलिटी संग करार

टाटा मोटर्स ने ऐप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली कंपनी प्रकृति ई-मोबिलिटी से करार किया है। इसके तहत प्रकृति ई-मोबिलिटी राष्ट्रीय राजधानी में अपनी सेवाओं के लिए टिगोर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का इस्तेमाल करेगी। कंपनी ने बयान में कहा कि टिगोर ईवी की 160 वाहनों की पहली खेप जनवरी 2020 से सड़कों पर दौड़ेगी। टाटा मोटर्स के अध्यक्ष (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कारोबार और कॉरपोरेट रणनीति) शैलेश चंद्र ने इस भागीदारी पर कहा, 'टिगोर ईवी प्रकृति ई-मोबिलिटी के बेड़े में एक मूल्यवान वाहन साबित होगी। यह बड़े स्तर पर आ रही मांग को पूरा करेगी और और वाणिज्यिक ग्राहकों को अधिक राजस्व की संभावना उपलब्ध कराएगी।' उन्होंने कहा कि टिगोर ईवी से कंपनी न केवल अपने कारोबारी लक्ष्य को हासिल कर पाएगी बल्कि इससे वह पर्यावरण के अनुकूल मोबिलिटी समाधान के उद्देश्य को भी पूरा कर पाएगी। प्रकृति ई-मोबिलिटी के सह संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमिष त्रिवेदी ने कहा कि कंपनी शून्य उत्सर्जन में विश्वास रखती है। ईवी के परिचालन की कम लागत पासा पलटने वाली साबित होगी। *भाषा*

जूमकार अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने की तैयारी में

समरीन अहमद
बेंगलूरु, 27 दिसंबर

सिकोया कैपिटल और महिंद्रा ऐंड महिंद्रा के निवेश वाली सेल्फ-ड्राइविंग कार रेंटल फर्म जूमकार इलेक्ट्रिक वाहन श्रेणी में उतरने और अपने बेड़े में 2,500 से 3,000 इलेक्ट्रिक वाहन जोड़ने की योजना बना रही है। बेंगलूरु की यह कंपनी फिलहाल 500 इलेक्ट्रिक वाहनों का परिचालन करती है। कंपनी इसमें सालाना आधार पर चार गुना वृद्धि होने का दावा करती है।

जूमकार घंटे, दिन, सप्ताह और महीने के आधार पर कार किराये पर देती है। इस प्लेटफॉर्म पर कंपनी के पास महिंद्रा ई2ओ प्लस और टाटा ई टिगोर उपलब्ध है जिसके लिए वह 15 से 20 हजार रुपये प्रति महीने सब्सक्रिप्शन शुल्क वसूलती है। कंपनी इलेक्ट्रिक वाहनों के अपने बेड़े में जल्द ही टाटा नेक्सन को शामिल करने की योजना बना रही है।

जूमकार के सह-संस्थापक एवं सीईओ ग्रेग मॉरन ने कहा, 'इलेक्ट्रिक वाहनों की रफ्तार लगातार बढ़ेगी और मौजूदा रुझानों के आधार पर हम अगले 5 से 6 महीनों में 100 फीसदी इलेक्ट्रिक के करीब होंगे।' फिलहाल कंपनी के प्लेटफॉर्म पर महज 5 फीसदी कार ही इलेक्ट्रिक वाहन हैं जबकि इन कारों के लिए विकल्प चुनने वाले उपयोगकर्ताओं की तादाद 10 से 15 फीसदी है। नवंबर में टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन ने अपने दैनिक कामकाज एवं रखरखाव कार्यों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल के लिए जूमकार के साथ करार किया था। जूमकार के 12 वाहनों के साथ इस परियोजना की शुरुआत भी हो चुकी है।

राइड-हेलिंग ऐप ओला भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर सवार हो रही है। कंपनी ने ओला इलेक्ट्रिक नाम से अपनी इलेक्ट्रिक वाहन परियोजना शुरू की है। कंपनी ने दैनिक मोबिलिटी के लिए 2021 तक 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को उतारने का लक्ष्य रखा है। उबर ने भी हैदराबाद में अपने प्लेटफॉर्म पर 50 एमऐंडएम इलेक्ट्रिक वाहनों को तैनात किया है। कंपनी अन्य शहरों में भी इलेक्ट्रिक वाहन उतारने की योजना बना रही है।

विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ेगा। बीआईएस रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार, 2019-2030 के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार 53.64 फीसदी सीएजीआर के साथ बढ़ने की उम्मीद है।

स्टार्टअप ने जुटाए 14.5 अरब डॉलर

पीरजादा अबरार
बेंगलूरु, 27 दिसंबर

- स्टार्टअप द्वारा कुल कोष उगाही के संदर्भ में दशक में 25 गुना वृद्धि दर्ज की गई
- कुल कोष उगाही में बेंगलुरु की कंपनियों का योगदान लगभग 50 प्रतिशत रहा, जिसके बाद दिल्ली और मुंबई का स्थान रहा

मौजूदा दशक समाप्त होने वाला है। स्टार्टअप कंपनियों द्वारा कुल कोष उगाही के संदर्भ में इस दशक में 25 गुना की तेजी दर्ज की गई। जहां वर्ष 2010 में यह कोष उगाही महज 55 करोड़ डॉलर थी, वहीं 2019 में 14.5 अरब डॉलर रही।

आंकड़ा विश्लेषण कंपनी ट्रैक्सन द्वारा तैयार 'इंडिया टेक एनुअल फैक्टशीट-2019' के अनुसार, इस साल स्टार्टअप कंपनियों ने 1,185 फंडिंग राउंड में 14.5 अरब डॉलर की पूंजी जुटाई, जिनमें 459 कोष उगाही मामले सीरीज ए के तहत शामिल थे। यह 2018 में जुटाए गए 10.5 अरब डॉलर और 2017 में 10.4 अरब डॉलर की तुलना में बड़ी वृद्धि है।

स्टार्टअप की यूनिकॉर्न श्रेणी में हाल में शामिल होने वाली कंपनियों में बेंगलूरु की ऑनलाइन किराना रिटेलर बिगबास्केट, गुरुग्राम की लॉजिस्टिक स्टार्टअप डेल्हीवरी और दिल्ली की आई-वियर कंपनी लेंसकार्ट शामिल हैं जिनका मूल्यांकन सॉफ्टबैंक सौदे के साथ हाल में 1.5 अरब डॉलर को पार कर गया है।

इस साल मासायोशी सन-नियंत्रित सॉफ्टबैंक ने भारतीय स्टार्टअप में बड़ा निवेश किया। सबसे बड़ी कोष उगाही गुरुग्राम की हॉस्पिटैलिटी कंपनी ओयो रूम्स द्वारा की गई। ओयो रूम्स ने सीरीज-एफ राउंड में 1.5 अरब डॉलर की पूंजी जुटाई। यह पूंजी सॉफ्टबैंक, सिकोइया और लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स जैसे निवेशकों से जुटाई गई। सॉफ्टबैंक के साथ साथ एंट फाइनैंशियल और डिस्कवरी कैपिटल ने डिजिटल भुगतान कंपनी पेटीएम में 1 अरब डॉलर का निवेश किया।

बिजनेस-टु-बिजनेस ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक और मोबिलिटी कंपनियों ने भी निवेशकों से बड़ी पूंजी आकर्षित की। इस साल, डेल्हीवरी ने सॉफ्टबैंक विजन फंड के नेतृत्व वाले फंडिंग राउंड में 41.3 करोड़ डॉलर जुटाए। सॉफ्टबैंक ने बेंगलूरु की ऐप-आधारित टैक्सी सेवा प्रदाता की इलेक्ट्रिक वाहन इकाई ओला इलेक्ट्रिक में भी 25 करोड़ डॉलर का निवेश किया। इस सौदे के बाद कंपनी रातोंरात 'यूनिकॉर्न' श्रेणी में शामिल हो गई। बेंगलूरु की बिजनेस-टु-बिजनेस ई-कॉमर्स कंपनी उड़ान ने चीन की टेंसेंट के नेतृत्व वाले सीरीज डी फंडिंग राउंड में 58.5 करोड़ डॉलर जुटाए।

इस साल कानूनी चुनौतियों की वजह से ई-फार्मेसी सेगमेंट की स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं दिखा। हालांकि मुंबई की ऑनलाइन फार्मेसी स्टार्टअप फार्मईजी ने टेमासेक से 22 करोड़ डॉलर की पूंजी हासिल की।

ट्रैक्सन के अनुसार, बेहद लोकप्रिय बिजनेस मॉडलों के संदर्भ में, इस साल होटल एग्रीगेटरों ने बढ़त दर्ज की, जिसके बाद ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक, ऑनलाइन बी2बी मार्केटप्लेस और कैब-राइड हेलिंग स्पेस का स्थान रहा।

डॉलर बॉन्ड में इस साल पांच गुना वृद्धि

जश कृपलानी और अनूप रॉय
मुंबई, 27 दिसंबर

कम रेटिंग वाली कंपनियों के लिए पूंजी बाजार तक पहुंच का अभाव और विदेशी बाजारों में आकर्षक ब्याज दरों के कारण भारतीय कंपनियों ने 2019 में डॉलर बॉन्ड के जरिये 23.6 अरब डॉलर की रकम जुटाई जो पिछले साल के मुकाबले करीब 5 गुना अधिक है।

आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि बुनियादी ढांचा, बिजली, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) ओर धातु उद्योग की कंपनियों ने इस प्रकार के बॉन्ड जारी किए ताकि चालू वर्ष में वित्तीय जरूरतों को पूरा किया जा सके।

जेएम फाइनैंशियल के प्रबंध निदेशक एवं प्रमुख (संस्थागत निर्धारित आय) अजय मंगलुनिया ने कहा, 'वैश्विक स्तर पर ब्याज दरें अनुकूल रही हैं। उधारकर्ताओं के लिए लागत मायने रखता है। मुद्रा बाजार में स्थिरता और बेहतर फॉरवर्ड प्रीमियम के कारण हेजिंग लागत में कमी आई है।' घरेलू कंपनियां भी वाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) के जरिये विदेशी पूंजी बाजार में गोता लगा रही है।

वर्ष 2019 के पहले 10 महीने (जनवरी से अक्टूबर) के दौरान ईसीबी के जरिये भारतीय कंपनियों ने 46 अरब डॉलर जुटाए जबकि 2018 में पूरे वर्ष के दौरान 32.69 अरब डॉलर जुटाए गए थे। भारतीय कंपनियों के लिए दमदार मांग के संकेतक के तौर पर कम रेटिंग वाली कंपनियों के लिए इन योजनाओं पर अधिकतम ब्याज दर घटकर 11.65 फीसदी रह गई जो पिछले साल 15 फीसदी रही थी।

घरेलू मोर्चे पर एनबीएफसी को उचित दरों पर रकम जुटाने में सबसे अधिक परेशानी हो रही है क्योंकि म्युचुअल फंड और बैंक इस क्षेत्र में परिसंपत्ति बनाम देनदारी में अंतर संबंधी चिंताओं के कारण एनबीएफसी कंपनियों को ऋण देने से कतरा रहे हैं। पिछले साल उजागर हुए आईएलऐंडएफएस संकट के बाद स्थिति कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है।

एनबीएफसी क्षेत्र से इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनैंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनैंस और सोना गिरवी रखकर ऋण देने वाली कंपनी मुथूट फाइनैंस ने डॉलर बॉन्ड बाजार से 3 अरब डॉलर जुटाए। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि निकट भविष्य में ऐसे कई डॉलर बॉन्ड जारी किए जा सकते हैं।

डॉयचे बैंक एजी के ग्रुप ट्रेजरर दीक्षित जोशी ने कहा, 'वास्तव में कुछ एनबीएफसी के लिए हमने डॉलर बाजार को रफ्तार दी है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले छह से नौ महीनों के दौरान ऐसे कई बॉन्ड जारी किए जाएंगे।'

मुकेश अंबानी का पारिवारिक मामला

आयकर विभाग ने सात देशों से मांगी जानकारी

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 27 दिसंबर

- इसी साल 29 मार्च को मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी और उनके तीन बच्चों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था
- पिछले महीने इन देशों से मांगी गई जानकारी मुख्य तौर पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से संबंधित हैं
- आयकर विभाग ने इन देशों से कर संधि के तहत सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए निर्धारित प्रारूप में जानकारी मांगी है

आयकर विभाग ने मुकेश अंबानी के परिवार के सदस्यों के खिलाफ काला धन अधिनियम 2015 के तहत जारी एक मामले में सात देशों से विस्तृत जानकारी मांगी है। इस मामले में अंबानी परिवार के सदस्यों पर विदेशी आय एवं परिसंपत्तियों का खुलासा न करने का आरोप लगाया गया है। इन सात देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, स्विटजरलैंड, सैंट लुइस, मॉरिशस, लग्जमबर्ग और बेल्जियम शामिल हैं।

पिछले महीने इन देशों से मांगी गई जानकारी मुख्य तौर पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से संबंधित हैं। आयकर विभाग का कहना है कि इसका इस्तेमाल अंबानी परिवार के स्वामित्व वाली दो भारतीय कंपनियों- रिलायंस यूटिलिटीज ऐंड पावर (आरयूपीएल) और रिलायंस पोर्ट ऐंड टर्मिनल (आरपीटीएल) को वैश्विक डिपॉजिटरी रिसीट (डीजीआर) सहित 40 करोड़ डॉलर मूल्य के विदेशी फंड के हस्तांतरण के लिए किया गया।

आयकर विभाग ने इन देशों से कर संधि के तहत सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए निर्धारित प्रारूप में जानकारी मांगी है। इसके लिए एक पत्र प्रधान आयुक्त (आयकर), मुंबई-3 के कार्यालय से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के संयुक्त सचिव (विदेशी कर एवं कर अनुसंधान) को भेजा गया। सीबीडीटी के इस विभाग से कर संधियों के तहत सात देशों को जानकारी के लिए पत्र भेजे गए हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रवक्ता ने बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा ई-मेल के जरिये भेजी गई एक प्रश्नावली के जवाब में कहा, 'हम एक बार फिर इस आरोप का पुरजोर खंडन करते हैं कि मुकेश अंबानी के परिवार के किसी भी सदस्य के पास ऐसी कोई विदेशी आय अथवा परिसंपत्ति नहीं है जिसका खुलासा न किया गया हो। हमारे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं और वे केवल दुर्भावना के उद्देश्य से भेजे गए हैं। हमारे पास कानून के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार है।'

इसी साल 29 मार्च को मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी और उनके तीन बच्चों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

आयकर विभाग ने अपने विदेशी समकक्षों को भेजे गए पत्र में कहा है कि इस करदाता ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की जानकारियों का खुलासा नहीं किया जिसका संबंध केमैन आईलैंड की कंपनी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड (आईसीएल) है। इसके अलावा उन्होंने कंपनी की परिसंपत्तियों का ब्यौरा नहीं दिया जहां विभिन्न घरेलू एवं विदेशी उपक्रमों के जरिये लाभार्थी मालिक थे।

विभाग ने अमेरिका को भेजे गए अपने अनुरोध पत्र में कहा है, 'इस ट्रस्ट के लाभार्थी मालिक होने के नाते उनके बिना खुलासे वाली परिसंपत्तियों और विदेशी आय के लिए उन पर काला धन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर देनदारी बनती है। वर्ष 2002 में जारी जीडीआर से लेकर अब तक कर चोरी की वास्तविक रकम का आकलन करने के लिए पूरे लेनदेन में शामिल सभी कंपनियों की जानकारी हासिल करना जरूरी है।'

आयकर विभाग के अनुसार, अंबानी परिवार ने कारण बताओ नोटिस में लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है और उसने 7 जून को जीडीआर पेशकश दस्तावेज के साथ अन्य दस्तावेजों की प्रति भी जमा कराई है। करदाता की ओर से दी गई जानकारी के सत्यापन के लिए विभाग ने संबंधित देशों से विस्तृत जानकारी मांगी है।

उभरते बाजारों के मुकाबले भारतीय बाजार महंगे

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अप्रैल-अक्टूबर 2019 के दौरान भारतीय बाजार में 7.8 अरब डॉलर का निवेश किया

ऐश्ली कुटिन्हो
मुंबई, 27 दिसंबर

आरबीआई की वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट के अनुसार, मूल्यांकन के लिहाज से उभरते बाजारों का इक्विटी परिदृश्य विकसित बाजारों के मुकाबले आकर्षक दिख रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अपने उभरते बाजार प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारतीय बाजारों का मूल्यांकन कुछ हद तक महंगा दिख रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि कॉरपोरेट आय में तेजी आती है तो प्रमुख सूचकांकों का महंगा मूल्यांकन बरकरार रहेगा।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'बीएसई 500 सूचकांक की त्रैमासिक प्रति शेयर आय (ईपीएस) वृद्धि सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर बढ़ी, हालांकि निफ्टी-50 शेयरों के लिए इसमें कमी दर्ज की गई। इसके अलावा, 6 महीनों की अवधि के दौरान आगामी आय

के अनुमानों में भी गिरावट का रुझान दर्ज किया गया है।' विश्लेषकों के अनुसार, कॉरपोरेट आय और शेयर भाव के बीच अंतर बढ़ कर वर्ष के ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। उदाहरण के लिए, सेंसेक्स के लिए वर्ष की समाप्ति 29 गुना के पी/ई मल्टीपल के साथ हो सकती है, जो 25 वर्षों में सर्वाधिक है। इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों में यह तीसरी बार है जब सूचकांक के शेयरों ने सामूहिक तौर पर आय में सालाना आधार पर गिरावट दर्ज की। सूचकांक की कंपनियों ने कैलेंडर वर्ष 2015 और 2016 में आय में कमी दर्ज की थी, जिसके बाद कैलेंडर वर्ष 2017 और 2018 में सुधार देखने को मिला था।

एफएसआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018-19 के रुझान के विपरीत, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने अप्रैल-अक्टूबर 2019 के दौरान भारतीय शेयर बाजार में 7.8 अरब डॉलर का निवेश किया। वित्त वर्ष 2020 की पहली दो तिमाहियों में डेट और हाइब्रिड सेगमेंट में भी पूंजी प्रवाह आकर्षित हुआ। चालू वर्ष के दौरान हाइब्रिड योजनाओं में एफपीआई निवेश तेजी से बढ़ा और अक्टूबर 2019 के अंत तक 74.4 करोड़ डॉलर का कुल पूंजी प्रवाह दर्ज किया गया। हालांकि एफपीआई ने वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में 3.2 अरब डॉलर के शेयर बेचे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रिक्स देशों (चीन को छोड़कर) में, भारत जनवरी-सितंबर अवधि के दौरान इक्विटी और डेट सेगमेंट, दोनों में एफपीआई पूंजी प्रवाह आकर्षित करने वाला एकमात्र देश था, जबकि रूस में समान अवधि के दौरान डेट सेगमेंट में एफपीआई द्वारा सर्वाधिक बिकवाली की गई।

कुल जमाओं में बीमित जमाओं का हिस्सा 28.1 फीसदी

भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट से पता चला है कि मार्च 2019 के आखिर में कुल जमा आधार में बीमित जमाओं की हिस्सेदारी 28.1 फीसदी रही। इन जमाओं पर एक लाख रुपये प्रति खाते के हिसाब से बीमा कवर है। खाते के लिहाज से मार्च 2019 के आखिर में बीमित जमा 33.7 लाख करोड़ रुपये थी जबकि जमाओं का कुल आधार 120.05 लाख करोड़ रुपये की थी।

हालांकि अगर खातों की संख्या पर विचार किया जाए तो 1 लाख रुपये का बीमा कवर कुल खातों के 92 फीसदी को कवर करता है। 2018-19 में सदस्य बैंकों की तरफ से संग्रहित कुल प्रीमियम 12,040 करोड़ रुपये रहा। इस प्रीमियम में वाणिज्यिक बैंकों का योगदान 93 फीसदी रहा जबकि सहकारी बैंकों का योगदान 7 फीसदी रहा। वित्त वर्ष 2020 की पहली छमाही में कुल 6,484 करोड़ रुपये प्रीमियम हासिल हुए। बीएस

एनपीए बढ़ा मगर बैंक ज्यादा सुदृढ़

पृष्ठ-1 का शेष

आरबीआई गवर्नर दास ने कहा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की चिंताओं को लेकर बाजार का रुख अब बदल रहा है। ये कंपनियां निरंतर अपने कारोबारी मॉडलों का पुनर्गठन कर रही हैं। सितंबर में बैंकों की उधारी की वृद्धि दर सालाना आधार पर 8.7 फीसदी रही जबकि जमाओं में 10.2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 2016-17 की दूसरी तिमाही के बाद यह पहला मौका है जब उधारी वृद्धि जमा वृद्धि से कम रही। वाणिज्यिक क्षेत्र में सभी श्रेणियों में क्रेडिट में कमी आई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रेडिट उठाव और जीडीपी वृद्धि में संबंध को देखते हुए वाणिज्यिक क्षेत्र में ऋण के प्रवाह में सुस्ती को दूर करने की जरूरत है। मार्च और सितंबर 2019 के बीच जीएनपीए अनुपात 9.3 फीसदी पर बरकरार रहा लेकिन बैंकिंग तंत्र का प्रोविजन कवरेज अनुपात (पीसीआर) मार्च 2019 के 60.5 फीसदी की तुलना में सितंबर 2019 में बढ़कर 61.5 फीसदी हो गया। यह बैंकिंग क्षेत्र के बढ़ते लचीलेपन का संकेत है। वित्तीय व्यवस्था में विभिन्न संस्थाओं के बीच द्विपक्षीय निवेश में मामूली गिरावट आई। भुगतान के मामले में निजी क्षेत्र के बैंकों की वृद्धि सालाना आधार पर सबसे अधिक रही जबकि प्राप्तियों के मामले में बीमा कंपनियों ने बाजी मारी। अंतर बैंक बाजार का आकार लगातार सिकुड़ रहा है और सितंबर अंत तक बैंकिंग क्षेत्र की कुल परिसंपत्तियों में इसका हिस्सा 4 फीसदी से भी कम रह गया है।

इस कमी के साथ-साथ सरकारी बैंकों के बेहतर पूंजीकरण से मार्च 2019 की तुलना में वित्तीय क्षेत्र में संचारी जोखिम कम हुआ है। फिर भी कई बैंकों में पूंजी पर्याप्तता अनुपात सितंबर 2020 में 9 फीसदी के न्यूनतम नियामकीय स्तर से कम हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर वृहद आर्थिक परिदृश्य बदतर होता है तो पांच बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9 फीसदी से नीचे जा सकता है।

बड़ी एनबीएफसी की नाकामी का नहीं पड़ेगा बैंकों पर असर

निधि राय
मुंबई, 27 दिसंबर

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट 2019 में कहा है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के दबाव की जांच से पता चलता है कि करीब 8.6 फीसदी वैयक्तिक एनबीएफसी न्यूनतम 15 फीसदी पूंजी की नियामकीय अनिवार्यता का अनुपालन नहीं कर पाएंगी। करीब 14.2 फीसदी कंपनियां न्यूनतम नियामकीय सीआरएआर नियमों का अनुपालन नहीं कर पाएंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकतम क्षमता वाली एनबीएफसी की नाकामी से बैंकिंग व्यवस्था का नुकसान कुल टियर-1 पूंजी का 2.5 फीसदी होगा। अधिकतम क्षमता वाली हाउसिंग फाइनैंस कंपनियों की नाकामी से बैंकिंग व्यवस्था का नुकसान उसके कुल टियर-1 पूंजी का 4.6 फीसदी होगा। दोनों में से कोई भी स्थिति हो यानी एनबीएफसी या एचएफसी नाकाम होगी तो कोई भी अतिरिक्त बैंक नाकाम नहीं होगा।

पिछले छह महीने में इस तरह का सुधार देखने को मिला है क्योंकि जून में आरबीआई की वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट में कहा गया था कि एचएफसी की नाकामी से बैंकिंग व्यवस्था की कुल टियर-1 पूंजी का 5.8 फीसदी नुकसान होगा और एक बैंक नाकाम होगा। एनबीएफसी की नाकामी से कुल टियर-1 पूंजी का 2.7 फीसदी नुकसान होगा और एक बैंक नाकाम होगा।

एनबीएफसी क्षेत्र का सकल एनपीए अनुपात मार्च 2019 के आखिर के 6.1 फीसदी से बढ़कर सितंबर 2019 के आखिर में 6.3 फीसदी पर पहुंच गया। शुद्ध एनपीए अनुपात हालांकि मार्च 2019 और सितंबर 2019 के बीच 3.4 फीसदी पर स्थिर रहा। सितंबर 2019 के आखिर में एनबीएफसी क्षेत्र का सीआरएआर 19.5 फीसदी था, जो मार्च 2019 के आखिर में 20 फीसदी रहा था।

एनबीएफसी में वित्तीय क्षेत्र के निवेश पर टिप्पणी करते हुए आरबीआई ने कहा है कि वित्तीय व्यवस्था से फंडों की शुद्ध देनदार एनबीएफसी रही है और सकल भुगतानयोग्य रकम 8,29,468 करोड़ रुपये रहा है जबकि सकल प्राप्तियां करीब 66,635 करोड़ रुपये और ये आंकड़े सितंबर 2019 के आखिर के हैं। सकल भुगतानयोग्य रकम पर नजर डालने से संकेत मिलता है कि 48.4 फीसदी फंड एससीबी से हासिल किए गए जबकि 26 फीसदी एएमसी-एमएफ से और 21.3 फीसदी बीमा कंपनियों से। वित्त वर्ष 2018-19 में एससीबी की हिस्सेदारी बढ़ी थी, लेकिन 2019-20 की पहली छमाही में इसमें मामूली गिरावट आई है। एएमसी-एमएफ की हिस्सेदारी पिछली कुछ तिमाहियों से घट रही है।

एनबीएफसी के बाद एचएफसी वित्तीय व्यवस्था से कर्ज लेने वाला दूसरा देनदार है और सितंबर 2019 के आखिर में सकल भुगतानयोग्य रकम 5,90,039 करोड़ रुपये थी जबकि सकल प्राप्तियां 33,110 करोड़ रुपये। एचएफसी को रकम मुहैया कराने में एएमसी-एमएफ की हिस्सेदारी पिछले साल तेजी से घटी और सिर्फ वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में इसमें मामूली बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसकी तुलना में एससीबी की सापेक्षिक हिस्सेदारी में बढ़ोतरी नजर आई है, लेकिन सितंबर 2019 में यह घटकर 40.9 फीसदी रह गई।

अदाणी ने खरीदी स्नोमैन लॉजिस्टिक्स की हिस्सेदारी

अदिति दिवेकर
मुंबई, 27 दिसंबर

अदाणी पोर्ट्स ऐंड एसईजेड लिमिटेड (एपीएसईजेड) की इकाई अदाणी लॉजिस्टिक्स ने आज ऐलान किया कि उसने स्नोमैन लॉजिस्टिक्स की 40.25 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण गेटवे डिस्ट्रिपार्क्स लिमिटेड से 296 करोड़ रुपये में करने के लिए करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

44 रुपये प्रति शेयर की खरीद कीमत 27 दिसंबर 2019 के बाजार भाव के मुकाबले 8 फीसदी प्रीमियम दर्शाता है जबकि 60 दिन का वॉल्यूम भारांकित औसत कीमत के मुकाबले 12 फीसदी प्रीमियम दर्शाता है। कंपनी ने एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी।

एपीएसईजेड के मुख्य कार्याधिकारी के हवाले से कहा गया है, यह अधिग्रहण भारत में एकीकृत लॉजिस्टिक्स सेवा में अग्रणी बनने और पोर्ट गेट से कस्टमर गेट तक पहुंचने की हमारी रणनीति के मुताबिक है। भारत में उपभोक्ता के जरिये आगे बढ़ने वाली मांग को देखते हुए कस्टमर गेट स्ट्रैटिजी में कोल्ड चेन अहम उत्पाद है।

अदाणी की तरफ से इस अधिग्रहण का ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब भारत आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है और विभिन्न

अगले पांच साल में कंपनी अपनी क्षमता दोगुनी करेगी

क्षेत्रों की देसी कंपनियां पूंजीगत खर्च में कटौती कर रही हैं क्योंकि उन्हें स्पष्ट रूप से मजबूत राजस्व नजर नहीं आ रहा है।

इस लेनदेन के तहत अदाणी लॉजिस्टिक्स नियम के मुताबिक कंपनी की अधिकतम 26 फीसदी सार्वजनिक शेयरधारिता के लिए अनिवार्य खुली पेशकश लाएगी। अदाणी का कहना है कि यह सौदा 31 मार्च 2020 तक पूरा हो सकता है। अदाणी ने कहा, हम अगले पांच साल में कोल्ड चेन में अपनी क्षमता दोगुनी करेंगे।

स्नोमैन लॉजिस्टिक्स की मौजूदगी देश के 15 शहरों में है। प्रवर्तक गेटवे डिस्ट्रिपार्क्स ने स्नोमैन लॉजिस्टिक्स को साल 2014 में सूचीबद्ध कराया था और लंबी अवधि में उसकी योजना पड़ोस में विस्तार करने की थी।

आयकर विभाग की तलाशी में किया पूरा सहयोग : डिशमैन

कंपनी ने राजस्व में 8-10 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान दोहराया

विनय उमरजी
अहमदाबाद, 27 दिसंबर

आयकर विभाग के तलाशी अभियान पर डिशमैन कार्बोजेन एमसिस लिमिटेड ने संस्थागत निवेशकों को बताया है कि अधिकारियों को उन्होंने पूरा सहयोग दिया और हर तरह के दस्तावेज मुहैया कराया।

संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों संग बातचीत में डिशमैन ने कहा कि आईटी का तलाशी अभियान अप्रत्याशित था क्योंकि कंपनी को कर मांग का कोई पूर्व नोटिस नहीं मिला था। कंपनी ने निवेशकों से कहा कि उसे आईटी की जांच का कोई प्रतिकूल नतीजा नहीं मिलने का अनुमान है।

बीएसई को भेजी सूचना में कंपनी ने गुरुवार को कहा था कि आईटी अधिकारियों ने कंनपी के कार्यालयों और विनिर्माण स्थल पर तलाशी अभियान चलाया।

कंपनी ने बीएसई को भेजी सूचना में कहा है, कंपनी ने आयकर विभाग के अधिकारियों को तलाशी के दौरान पूरा सहयोग दिया और मांगे गए दस्तावेज मुहैया कराए। तलाशी अभियान 25 दिसंबर 2019

शुक्रवार को कंपनी का शेयर 3.59 फीसदी चढ़कर 82.15 रुपये पर बंद हुआ

को चला। डिशमैन कार्बोजेन एमसिस लिमिटेड कंपनी परिचालन के अच्छे मानकों व वित्तीय अनुशासन का पालन करती है। अपने साझेदारों, निवेशकों, वित्तीय संस्थानों और क्लाइंटों के साथ हम पारदर्शी लेनदेन करते हैं।

आईटी के अभियान पर टिप्पणी करते हुए डिशमैन समूह के चेयरमैन जनमेजय व्यास ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा कि कंपनी अब विभाग के असेसमेंट की प्रतीक्षा कर रही है। हमने आईटी विभाग की सभी पूछताछ का कामयाबी के साथ जवाब दिया क्योंकि हमारी टीम मजबूत लेखा प्रक्रिया का पालन करती है और खाते भी डिजिटल हैं। अब हम विभाग के आकलन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसके मुताबिक जवाब देंगे।

ब्रोकिंग फर्म निर्मल बांग ने कहा, डिशमैन का मानना है कि कंपनी के स्वचालित खाते आईटी विभाग की डेटा की जरूरतें तत्काल पूरी कर देगा। तलाशी अभियान के दौरान ट्रांसफर प्राइसिंग, गुडविल जैसे पहलू की जांच हुई। ट्रांसफर प्राइसिंग के संबंध में कंपनी ने संकेत दिया है कि ज्यादातर इलाकों में उनका परिचालन कमोबेश एक ही कर दर पर होता है। भारत के मौट की तरह ही ब्रिटेन, स्विटजरलैंड और नीदरलैंड में भी कर की दर क्रमश: 19 फीसदी, 20 फीसदी और 25 फीसदी है।

कंपनी ने इस बैठक में सूचित किया कि आईटी के अभियान का विस्तार प्रवर्तक समूह की अन्य इकाई तक नहीं हुआ, न ही उसके कारोबारी परिचालन आदि पर उसका असर पड़ा है। हालांकि यह अभियान करीब एक हफ्ते चला।

आईटी के अभियान पर कंपनी के जवाब के कारण शुक्रवार को उसका शेयर 3.59 फीसदी चढ़कर 82.15 रुपये पर बंद हुआ।

आईओबी के लिए 4,360 करोड़ रुपये मंजूर

बीएस संवाददाता
चेन्नई, 27 दिसंबर

इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार ने बैंक के लिए 4,360 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

बैंक ने कहा है, 'हम यह बताना चाहते हैं कि बैंक को 26 दिसंबर, 2019 को केंद्र सरकार से 4,360 करोड़ रुपये की पूंजी लगाए जाने के बारे में पत्र मिला। इस पत्र में सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक के इक्विटी शेयरों (विशेष प्रतिभूतियां/बॉन्ड) के तरजीही आवंटन में केंद्र सरकार द्वारा निवेश के तौर पर इस रकम का योगदान किए जाने की घोषणा की गई है।'

सरकार ने यूको बैंक में भी 2,142 करोड़ रुपये डालने की मंजूरी दी है

आईओबी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी कर्णम शेखर ने शुरू में कहा था कि बैंक द्वारा जल्द तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के दायरे से बाहर आने और शुद्ध मुनाफा दर्ज किए जाने की संभावना है। 30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही में बैंक का कर-पूर्व नुकसान बढ़कर 2250.03 करोड़ रुपये हो गया जो एक साल पहले 712.41 करोड़ रुपये था। बैंक तिमाही के दौरान अपनी सकल एनपीए और शुद्ध एनपीए अनुपात को घटाकर 20 प्रतिशत और 9.84 प्रतिशत करने में सफल रहा। बैंक को एनपीए स्तरों में और कमी आने की संभावना है। इसके अलावा सरकार ने यूको बैंक में भी 2,142 करोड़ रुपये डालने की मंजूरी दी है। इसकी घोषणा इस साल अगस्त में की गई थी।

बीएस बातचीत

नकदी में सुधार से मिडकैप और स्मॉलकैप को होगा ज्यादा फायदा

एडलवाइस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के डिप्टी सीईओ **शिव सहगल** ने कहा है कि नकदी के परिदृश्य में हो रहा सुधार बाजार के लिए सकारात्मक है। **ऐश्ली कुटिन्हो** को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि बाजार पूंजीकरण-जीडीपी के लिहाज से भारत 77 फीसदी पर कारोबार कर रहा है, जो उसका लंबी अवधि का औसत है और महंगा नहीं है। बातचीत के मुख्य अंश...

साल 2020 के लिए बाजार को लेकर आपका क्या नजरिया है?

आर्थिक सुस्ती के बीच इस साल निफ्टी करीब 12 फीसदी चढ़ा है, जो साल 2018 के आखिर में की गई उम्मीद के मुकाबले ज्यादा चढ़ा। साल 2018 में बाजार की तेजी व्यापक रही थी। पिछले साल फेडरल रिजर्व की ब्याज दर बढ़ोतरी व मात्रात्मक सख्ती की वजह से उभरते बाजारों से नकदी की निकासी हुई, जिससे कमजोर बढ़त व परिसंपत्ति बाजार के प्रदर्शन पर असर पड़ा। हालांकि साल 2019 में फेड ने अपना रुख बदल लिया, ब्याज दरें तीन बार घटाई और बैलेंस शीट में विस्तार किया। इन वजहों से नकदी परिदृश्य में सुधार हो रहा है, जो साल 2020 को लेकर हमें आशावादी बना रहा है। मुख्य मूल्यांकन एक साल आगे की आय के 18 गुने पर ऊंचा नजर आ रहा है। हालांकि इंडेक्स के भीतर ध्रुवीकरण को ढक देता है। बाजार पूंजीकरण-जीडीपी के लिहाज से भारत 77 गुने पर कारोबार कर रहा है, जो उसकी लंबी अवधि का औसत है पर महंगा नहीं है।

मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों को लेकर आपका क्या नजरिया है?

मुझे लगता है कि नकदी के परिदृश्य में सुधार का सबसे ज्यादा फायदा मिडकैप व स्मॉलकैप शेयरों को होगा। ये शेयर जिस भाव पर कारोबार कर रहे हैं उसके मूल्यांकन में भारी छूट को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह सिर्फ समय की बात है जब वे लार्जकैप के पास पहुंच जाएंगे।

आप किन क्षेत्रों पर दांव लगा रहे हैं?

वैश्विक बाजारों पर केंद्रित क्षेत्रों का प्रदर्शन साल 2020 में अच्छा रहेगा और उस सीमा तक धातु, एक्सपोर्ट ऑटो और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल्स का परिदृश्य शानदार नजर आ रहा है। हालांकि इनमें से कुछ ने असर दिखाया है, लेकिन हमें लगता है कि अभी कुछ और तेजी की गुंजाइश है। पिछले दो साल में बाजारों में दिखा ध्रुवीकरण पलट गया है और निवेशकों को हर क्षेत्र में पिछड़ने वाले शेयर पर नजर डालना चाहिए। इंडस्ट्रियल्स, एनबीएफसी और कॉरपोरेट बैंकों के मूल्यांकन पर दबाव है और साल 2020 में इसमें बदलाव होगा। कुल मिलाकर मूल्यांकन वाला शेयर साल 2020 में गुणवत्ता वाले शेयरों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करेगा।

उपभोक्ताओं का खर्च घटा है। इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं?

उपभोक्ता खर्च में आई मौजूदा नरमी कुछ समय से बनी हुई है। हमारा निवेश व निर्यात चक्र साल 2012 में सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा था और तब से हमने मंदी का लंबा वक्त देखा है। यही क्षेत्र रोजगार मुहैया कराता है। हालांकि साल 2018 तक उपभोग का स्तर ठीक-ठाक था क्योंकि आम परिवारों की नकदी बढ़ी थी और नकदी सहज थी। पिछले एक साल में नकदी का उपभोग पर असर पड़ा है। हालांकि नकदी में सहता के बाद मुझे लगता है कि उपभोग और कुल आर्थिक रफ्तार जल्द स्थिर होगी।

सितंबर के बाद से आई तेजी को देखते हुए क्या हम तेज गिरावट को लेकर अतिसंवेदनशील बन गए हैं?

बाजार मूल रूप से आगे की राह देखता है और वास्तविक अर्थव्यवस्था के बजाय नकदी पर त्वरित प्रतिक्रिया जताता है। मुझे लगता है कि नकदी की स्थिति ठीक बनी रहेगी और आर्थिक रफ्तार स्थिर होगी। ऐसे में उस सीमा तक मुझे बाजार की तेजी को लेकर कम चिंता होगी। ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सितंबर से आ रही तेजी ज्यादा व्यापक है, न कि महज 10 अग्रणी शेयरों तक सीमित है।

बैंक समर्थित ब्रोकरों को नए क्लाइंट मिलने की आस

कार्वी घटनाक्रम के बाद भरोसा और मार्जिन सुविधा तक पहुंच से निवेशक उनकी ओर आएंगे

सुंदर सेतुरामन और जश कृपलानी
मुंबई, 27 दिसंबर

बैंक समर्थित ब्रोकरेज की बाजार हिस्सेदारी

ब्रोकरेज	बाजार हिस्सेदारी (फीसदी)*
जीरोधा	12.3
आईसीआईसीआई सिक्यो.	10.3
एचडीएफसी सिक्यो.	7.1
शेयरखान	5.4
कोटक सिक्योरिटीज	5.3
ऐक्सिस बैंक	3.4

* सक्रिय क्लाइंट के आधार पर
स्रोत : एनएसई, आईसीआईसीआई डायरेक्ट रिसर्च

बैंक समर्थित ब्रोकिंग हाउस को बाजार हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि कार्वी घटनाक्रम के बाद अपने निवेश की सुरक्षा को लेकर चिंतित निवेशक अपना खाता छोटे ब्रोकिंग हाउस से उनके यहां शिफ्ट कर सकते हैं।

अभी बैंक समर्तित चार अग्रणी ब्रोकिंग हाउस के पास सक्रिय क्लाइंटों का एक चौथाई है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी धीरज रेलि ने कहा, पिछले एक महीने में हमें नए खाते मिले हैं। कुछ ग्राहक हैं जो हमारे यहां खाते हस्तांतरित कर रहे हैं। साथ ही नए खाते भी खुल रहे हैं। उन्होंने कहा, कार्वी घटनाक्रम के बाद निवेशक वैसे ब्रोकिंग हाउस की तरफ देख रहे हैं जहां फंड की सुरक्षा को लेकर वे ज्यादा आश्वस्त हो सके।

इस बीच, छोटे ब्रोकिंग हाउस को ज्यादा परिचालन खर्च का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि सेबी कार्वी जैसे घटनाक्रम को रोकने के लिए नियम सख्त करने पर विचार कर रहा है। यह कहना है उद्योग के सूत्रों का। एक छोटे ब्रोकिंग हाउस के प्रमुख ने कहा, हमें अनुपालन की लागत बढ़ने का अंदेशा है, जो हमारे लिए माहौल और चुनौतीपूर्ण बना देगा।

उद्योग के प्रतिभागियों ने कहा कि कार्वी घटनाक्रम ने मार्जिन फंडिंग के जोखिम को रेखांकित किया, जो कुछ ब्रोकरों के लिए आय के स्रोत के तौर पर उभरा है। एक प्रतिभागी ने कहा, कुछ मामलों में मार्जिन फंडिंग की आय में हिस्सेदारी एक चौथाई तक रही है। मार्जिन फं डिंग पर प्रतिफल 12 से 18 फीसदी तक है। हालांकि आय का यह स्रोत गैर-बैंक ब्रोकिंग हाउस के लिए समाप्त हो सकता है क्योंकि सेबी ने क्लाइंटों को मार्जिन की सुविधा देने के लिए ब्रोकरों को क्लाइंट के शेयर को जमानत के तौर पर रखने से रोकना का कदम उठाया है।

आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने एक नोट में कहा, क्लाइंट के फंडों के प्रबंधन को लेकर सेबी की तरफ से नियमों से सख्ती से क्लाइंट के शेयरों को गिरवी रखना, ब्रोकर की तरफ से सीधी उधारी आदि समाप्त हो जाएगी। ब्रोकरों को बैंक या एनबीएफसी संग गठजोड़ करना होगा क्योंकि वे ही क्लाइंटों का शेयर गिरवी रखकर फंड मुहैया करा सकते हैं।

धीरज रेलि ने कहा, बैंक समर्थित ब्रोकिंग हाउस जरूरत के समय कम लागत पर रकम जुटा सकते हैं और क्लाइंटों को मार्जिन की सुविधा दे सकते हैं।

छोटे ब्रोकरों ने कहा कि सेबी के नए नियम के तहत जरूरी निवेशकों से अग्रिम मार्जिन (खरीद व बिक्री दोनों के लिए) से उन्हें झटका लगेगा क्योंकि वे बेहतर मार्जिन सुविधा की पेशकश वाले ब्रोकरों का विकल्प चुन सकते हैं।

ब्रोकरों ने लाभ में गिरावट के लिए नकदी वॉल्यूम में गिरावट का भी उदाहरण दिया (जो अपेक्षाकृत ज्यादा मार्जिन की पेशकश करते हैं)। रोजाना औसत कारोबार की हिस्सेदारी के तौर पर नकदी वॉल्यूम करीब दो फीसदी है और यह जानकारी आईसीआईसीआई डायरेक्ट के नोट से मिली। इस बीच, उच्च मार्जिन वाला डिलिवरी ट्रेड और घटा है और नकदी वॉल्यूम में उसकी हिस्सेदारी 10 साल के निचले स्तर के आसपास है।

साल 2014-15 में नकदी बाजार में ब्रोकरों की संख्या 5,899 थी, जो 31 दिसंबर 2018 तक 53 फीसदी घटकर 2,734 रह गई। सेबी के आंकड़ों से यह जानकारी मिली।

रेलवे की कमजोर वित्तीय स्थिति से चिंता

शाइन जैकब
नई दिल्ली, 27 दिसंबर

रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन की चर्चा के बीच भारतीय रेलवे की सालाना योजना चिंताजनक तस्वीर पेश कर रही है। नैशनल ट्रांसपोर्टर की बजट से इतर संसाधनों (ईबीआर)पर निर्भरता बढ़ रही है और पूंजीगत व्यय में आंतरिक संसाधनों का हिस्सा घट रहा है।

इसी तरह से रेलवे का परिचालन अनुपात (परिचालन व्यय और परिचालन राजस्व का अनुपात) चालू वित्त वर्ष के दौरान पहले ही 100 प्रतिशत पार कर चुका है। इससे संकेत मिलते हैं कि रेलवे ने अब तक जितना कमाया है, उससे ज्यादा खर्च किया है। वित्त वर्ष 2018-19 में परिचालन अनुपात 97.3 प्रतिशत था, जबकि 2017-18 में 98.4 प्रतिशत था।

2018-19 की वास्तविक प्राप्तियों के हिसाब से देखें तो पूंजीगत व्यय में आंतरिक संसाधनों का प्रतिशत घटकर 3.5 रह गया जो 2015-16 में 18 प्रतिशत था। वहीं दूसरी ओर इस अवधि के दौरान योजनागत पूंजीगत व्यय में ईबीआर पर निर्भरता 42 प्रतिशत से बढ़कर 57 प्रतिशत हो गई है। 2019-20 में इसमें आगे और बढ़ोतरी होने की संभावना है। ईबीआर में ज्यादा हिस्सा भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) और इंस्टीट्यूशनल फाइनैंस द्वारा एलआईसी जैसे कारोबारियों से ली गई उधारी का है।

रेलवे के पूर्व वित्त आयुक्त आर शिवदासन ने कहा, '2006-07 में आंतरिक कमाई की हिस्सेदारी 35-40 प्रतिशत के उच्च सस्तर पर थी। इसका गिरकर 3.5 प्रतिशत पर आना चिंताजनक है। इसकी एक बड़ी वजह यह रही है कि उसके बाद की सरकारों ने यात्री किराया बढ़ाने में सुस्ती दिखाई, जो ममता बनर्जी के कार्यकाल से शुरू हुआ।'

उन्होंने कहा कि उधारी बढ़ना निश्चित रूप से मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के मुताबिक है। अगर इस धन का इस्तेमाल समर्पित मालवाहक गलियारा (डीएफसी) जैसी परियोजनाओं में होता तो यह एक तरह का प्रोत्साहन होता, जिससे एक सुनिश्चित मुनाफे की उम्मीद की जा सकती है। आंतरिक संसाधनों से कमाई घटने की मुख्य वजह मालभाड़े और यात्रियों की आवाजाही में स्थिरता और यात्रियों को किराये में सब्सिडी दिया जाना है। एक अधिकारी ने कहा कि कमाई बढ़ाने के लिए यात्री किराये में जल्द ही सभी श्रेणियों में कम से कम 40 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। हालांकि रेलवे के प्रवक्ता ने कहा कि किराये को तार्किक बनाने का यह मतलब नहीं होता कि उसमें बढ़ोतरी ही हो।

रेलवे किस तरह से जुटाता है अपना पूंजीगत व्यय

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कुल पूंजीगत व्यय	ईबीआर का हिस्सा	आंतरिक संसाधन
2015-16	93,520	39,066	16,845
2016-17	1,09,935	52,578	12,155
2017-18	1,01,986	55,498	3,070
2018-19	1,33,397	75,876	4,663
2019-20*	1,60,176	83,571	10,500

स्रोत : भारतीय रेल *बजट अनुमान

पूंजीगत व्यय में सरकार से मिलने वाला बजट समर्थन शामिल

1 अप्रैल से 10 दिसंबर 2019 के बीच कुल कमाई में 0.5 प्रतिशत की मामूली गिरावट हुई है और यह 2018-19 के 1,22,759.9 करोड़ रुपये से घटकर 1,22,108.8 करोड़ रुपये रह गई है। माल ढुलाई से कमाई में 2.94 प्रतिशत गिरावट आई है और यह इस अवधि के दौरान घटकर 79,297.88 करोड़ रुपये रह गई है, जो 2018-19 में 81,697.05 करोड़ रुपये थी।

एक अधिकारी ने कहा, 'सातवें वेतन आयोग के बाद खर्च बढ़ने और पेंशन पर व्यय बढ़ने और यात्रियों से कमाई कम रहने के कराण परिचालन मुनाफा प्रभावित हुआ है। माल ढुलाई से मिलने वाला राजस्व कम होने का भी असर रहा है, जो आर्थिक सुस्ती की वजह से प्रभावित हुआ है।'

रेलवे की सालाना पेंशन देनदारी करीब 30,000 करोड़ रुपये है, जबकि उसके कर्मचारियों पर आने वाला खर्च करीब 79,000 करोड़ रुपये है। रेलवे बोर्ड ने वित्त मंत्रालय से मांग की है कि वह पेंशन में अंशदान करे, जिससे कि परिचालन अनुपात 70 प्रतिशत तक लाया जा सके। इसके साथ ही बोर्ड प्रदर्शन सूचकांकों को 90 प्रतिशत तक लाने पर भी काम कर रहा है, जिनमें परिटालन कुशलता में सुधार और ईंधन की लागत कम करना शामिल है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान यात्री कियारे से कमाई 4.21 प्रतिशत बढ़ी है और यह दिसंबर 2018-19 तक के 35,250.34 करोड़ रुपये से बढ़कर इस साल दिसंबर तक 36,732.83 करोड़ रुपये हो गया है। दिलचस्प है कि रेलवे की माल ढुलाई इस दौरान 1.19 प्रतिशत घटकर 8723.7 लाख टन रह गई है। माल ढुलाई में कमी की बड़ी वजह कोयले की ढुलाई में 3.2 प्रतिशत की गिरावट है, जो पिछले साल की समान अवधि के 4,349 लाख टन की तुलना में घटकर 4,202 लाख टन रह गई।

छोटे कारोबार की धारणा 1 साल के निचले स्तर पर

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 27 दिसंबर

चल रही आर्थिक मंदी की वजह से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) की धारणा वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में एक साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। एक प्रमुख तिमाही सर्वे में यह सामने आया है।

क्रिसिडएक्स सर्वे के 8वें संस्करण के मुताबिक दूसरी तिमाही में धारणा गिरकर 106 पर आ गईष जो पहली तिमाही के 120 की तुलना में कम है। इससे पता चलता है कि लगातार तीसरी तिमाही में धारणा कम हुई है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा तैयार किए गए इस सूचकांक में शून्य (एकदम नकारात्मक) से 200 (एकदम बेहतर) अंक दिया जाता है।

सिर्फ 29 प्रतिशत विनिर्माताओं ने कहा कि दूसरी तिमाही कारोबार के लिए उतनी ही बेहतर रही, जितनी पहली तिमाही थी। इसके परिणामस्वरूप इस तिमाही में सकारात्मक धारणा पिछली 5 तिमाहियों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। वाहन उपकरण, धातु एवं खनन, इंजीनियरिंग और पूंजीगत वस्तुओं के विनिर्माताओं ने सुस्त तिमाही बताई है। विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट बहुत तेज रही।

सेवा प्रदाताओं में सिर्फ 19 प्रतिशत फर्मों ने कहा कि दूसरी तिमाही अच्छी है, जबकि पहली तिमाही को 28 प्रतिशत लोगों ने बेहतर बताया था। इस क्षेत्र में प्रतिक्रिया देने वालों में वाणिज्यक सेवा, निर्माण व रियल एस्टेट, यात्रा व होटल और लॉजिस्टिक क्षेत्र ने ज्यादा आशावादी जवाब दिए।

क्रिसिल लिमिटेड के मुख्य परिचालन अधिकारी अमीश मेहता ने कहा, 'आठवें सर्वे के आंकड़ों को व्यापक आर्थिक परिदृश्य जैसे ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं द्वारा उत्पादन में कटौती से कल पुर्जों के इस्तेमाल पर असर, स्टील, जैसे जिंस से जुड़े क्षेत्रों में गिरावट, रत्न व आभूषण तथा होटलों की खपत आदि के मुताबिक देखे जाने की जरूरत है।'

नए प्रावधानों को मिल सकती है न्यायालय में चुनौती

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 27 दिसंबर

विशेषज्ञों का कहना है कि वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था के हाल के प्रावधान कड़े हैं, जिनमें अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि जीएसटी दाखिल न किए जाने की स्थिति में वे करदाता के बैंक खाते सहित उनकी संपत्तियां जब्त कर सकते हैं।

खेतान ऐंड कंपनी के पार्टनर अभिषेक रस्तोगी ने कहा कि यह संभव है कि इस व्यवस्था को न्यायालय में चुनौती मिल सकती है। रस्तोगी जीएसटी से जुड़े तमाम मामलों को लेकर न्यायालयों में बहस कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अनुपालन न करने पर बैंक खातों को जब्त करने, पंजीकरण रद्द करने जैसे फैसले बहुत कठोर हैं, जबकि उद्योग पहले से ही इस तरह के तमाम मसलों से जूझ रहा है।

पीएमसी बैंक घोटाले में 32 हजार पन्नों का आरोप पत्र

भाषा
मुंबई, 27 दिसंबर

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने करोड़ों रुपये के पंजाब एवं महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाले में पांच आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को यहां मेट्रोपोलिटन अदालत में 32 हजार पन्नों का आरोप पत्र दायर किया। आरोप पत्र में बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक जॉय थॉमस, पूर्व चेयरमेन वरयाम सिंह, बैंक के पूर्व निदेशक सुरजीत सिंह अरोड़ा के अलावा हाउसिंग डेवलपमेंट ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के प्रमोटर राकेश वधावन और सारंग वधावन का नाम है।

आरोपियों को ठगी, धोखाधड़ी, सबूत मिटाने और दस्तावेजों की जालसाजी समेत भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपित किया गया है। सितंबर में बैंक घोटाला सामने आते ही सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं।

इन पांचों आरोपियों के अलावा पुलिस ने बैंक के 7 अन्य अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ बाद में पूरक आरोप पत्र दायर किया जाएगा। 32 हजार पन्नों के आरोप पत्र में पीएमसी की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट, आरोपी बैंक अधिकारियों द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के दस्तावेज और एचडीआईएल तथा वधावन को अनुचित लाभ पहुंचाने के बदले उन्हें मिली रिश्वत की जानकारी शामिल है।

आरोप पत्र में बैंक खाताधारकों के बयानों समेत 340 गवाहों के बयान शामिल हैं। पुलिस ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत एक मजिस्ट्रेट के समक्ष चार महत्त्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज किए थे।

बेंगलूरु के रेलवे स्टेशनों पर मिलेंगे बाउंस के स्कूटर

पीरजादा अबरार
बेंगलूरु, 27 दिसंबर

मेट्रो स्टेशनों के बाद बाइक शेयरिंग स्टार्टअप बाउंस अब रेलवे स्टेशनों से भी सेवाएं देगी। एस्सेल और सिकोया समर्थित कंपनी ने कर्नाटक के रेलवे स्टेशनों पर स्कूटर शेयरिंग सेवा मुहैया कराने की प्रतिस्पर्धी बोली हासिल की है। इस तरह का सौदा हासिल करने वाला यह पहला स्टार्टअप है। कंपनी अपने परिचालन का विस्तार बेंगलूरु के 13 रेलवे स्टेशनों तक कर सकेगी, जिससे रेल यात्रियों को अपने घर तक पहुंचने की सहूलियत मिल सकेगी। बाउंस के सीईओ और सह संस्थापक विवेकानंद हल्लेकेरे ने कहा, 'बुनियादी ढांचे पर बोझ बढ़ने के साथ इस बात की तत्काल जरूरत है कि लोग व्यक्गित साधनों को छोड़कर सार्वजनिक परिवहन और साझा करने वाले वाहनों का इस्तेमाल करें।'

रिजर्व बैंक के मुताबिक वित्त वर्ष 2019 में दबाव वाली संपत्तियों की वसूली में हुआ मामूली सुधार

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान दबाव वाली संपत्तियों की वसूली मामूली बढ़ी है। इसकी प्रमुख वजह ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) के तहत समाधान है। विभिन्न व्यवस्थाओं के तहत मामले वसूली के लिए भेजे गए और इस दौरान इनकी संख्या मात्रा के हिसाब से 27 प्रतिशत बढ़ी है और मूल्य के आधार पर इसमें तीन गुना बढ़ी है। इसकी वजह से दिवाला प्रक्रिया में मामले बहुत ज्यादा बढ़े हैं। वित्त वर्ष 2019 में करीब 8.15 लाख करोड़ रुपये की दबाव वाली संपत्तियां वसूली प्रक्रिया में डाली गईं, जो वित्त वर्ष 2017-18 के 2.7 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 200 प्रतिशत से भी ज्यादा है। इसके साथ ही वसूली 70,819 करोड़ रुपये से भी ज्यादा बढ़ी है, जिसकी रिकवरी दर 42.5 प्रतिशत रही। बहरहाल वित्त वर्ष 19 में लोक अदालतों को छोड़कर प्रमुख समाधान व्यवस्थाओं से वसूली की दर कम हुई है। खासकर वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण और ब्याज व्यवस्था के तहत प्रतिभूतियों के प्रवर्तन से वसूली घटी है।

चित्रांकनः अजय मोहंती

सुब्रत पांडा

वित्त वर्ष 2019 में विभिन्न माध्यमों से एससीबी की एनपीए की वसूली

(राशि करोड़ रुपये में)

	2017-18				2018-19			
	भेजे गए मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली गई राशि	कुल शामिल राशि के प्रतिशत में वसूली गई राशि	भेजे गए मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली गई राशि	कुल शामिल राशि के प्रतिशत में वसूली गई राशि
लोक अदालतें	3,317,897	45,728	1,811	4.0	4,080,947	53,506	2,816	5.3
डीआरटी	29,345	1,33,095	7,235	5.4	52,175	3,06,499	10,574	3.5
सरफेसी ऐक्ट	91,330	81,879	26,380	32.0	248,312	2,89,073	41,876	14.5
आईबीसी	704*	9,929	4,926	49.6	1,135*	1,66,600	70,819	42.5
कुल	3,439,276	2,70,631	40,352	14.9	4,382,569	8,15,678	1,26,085	15.5

डीआरटी : कर्ज वसूली न्यायाधिकरण, सरफेसी ऐक्ट : वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूतियों पर ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम, 2002, *राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार किए गए मामले, एससीबीः अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

स्रोतः ऑफसाइट रिटर्न, रिजर्व बैंक, भारतीय ऋणशोधन अक्षमता और दिवाला बोर्ड

हॉलीवुड को टक्कर दे सकता है मनोरंजन उद्योग

पृष्ठ 1 का शेष

इसमें दूरसंचार, प्रौद्योगिकी और मीडिया कंपनियों के बीच दर्शकों को खींचने की होड़ मची है। गूगल, एमेजॉन, एटीऐंडटी, डिज्नी, कॉमकास्ट, ऐप्पल और नेटफ्लिक्स इसकी अगुआई कर रही हैं। ये कंपनियां अपना दायरा बढ़ाने के लिए दूसरी कंपनियों का अधिग्रहण कर रही हैं और पूरी दुनिया से कंटेंट बटोर रही हैं।

चीन से इतर भारत में विदेशी फिल्मों को लेकर किसी तरह की बंदिश नहीं है। हालांकि मनोरंजन उद्योग में 90 फीसदी से अधिक सामग्रियां स्थानीय ही होती हैं। दुनिया भर में मनोरंजन उद्योग जहां हॉलीवुड से अभिभूत दिखता है, वहीं भारत का रचनात्मक उद्योग का अपना 100 साल का समृद्ध इतिहास रहा है।

भारत उन गिने-चुने बाजारों में है जिसके पास स्थानीय स्तर पर मौलिक कहानियां हैं।

पिछले एक दशक में दंगल, गली बॉय, गैंग्स ऑफ वासेपुर, विकी डोनर, पीकू, मसान, अंधाधुन जैसी हिंदी फिल्में स्थानीय कहानी के आधार पर बनाई गई हैं। इसके साथ तमिल, मराठी, बांग्ला आदि भाषाओं में भी मौलिक कहानियों पर फिल्में बनी हैं।

यूट्यूब से लेकर नेटफ्लिक्स तक भारतीय दर्शकों और सामग्री निर्माताओं ने दुनिया को चकित किया है। यूट्यूब 1.8 अरब उपयोगकर्ताओं के साथ दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। यह खुला और ऑनलाइन ऑडिटोरियम की तरह है जहां कोई भी आकर अपनी प्रतिभा दिखा सकता है, जानकारियां साझा कर सकता है और वीडियो पोस्ट कर सकता है।

भारतीय संगीत फर्म टी-सीरीज दुनिया भर में सबसे अधिक देखा जाने वाला यूट्यूब चैनल है।

दूसरी ओर नेटफ्लिक्स है, जिस पर उच्च गुणवत्ता वाली मनोरंजक सामग्रियों का सबस्क्रिप्शन आधारित प्लेटफॉर्म है। इसके पास 18 भारतीय शो हैं जो निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं, वहीं 8 स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हैं। इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या 16 करोड़ है। मुख्य कंटेंट अधिकारी टेड सैरेनडॉस ने पिछले साल कहा था, 'सामग्री के लिहाज से भारत हमारा सबसे बड़ा बाजार है।'

पिछले महीने नेटफ्लिक्स के मुख्य कार्याधिकारी रीड हेस्टिंग्स ने घोषणा की थी कि नेटफ्लिक्स 2019 और 2020 में भारत में कंटेंट पर 3,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। मीडिया पार्टनर्स एशिया का अनुमान है कि 2024 तक ऑनलाइन वीडियो इकाइयों द्वारा भारत में करीब 1.4 अरब डॉलर का निवेश किया जा सकता है।आप तर्क दे सकते हैं कि 74,000 करोड़ रुपये का भारतीय

अगर भारतीय कहानीकार क्षमता का इस्तेमाल करने में सक्षम होते हैं तो भारतीय मनोरंजन उद्योग अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन बन सकता है

टेलीविजन उद्योग जो हर रात 3 से 6 घंटे तक नई सामग्रियां प्रस्तुत करता है, वह इससे कहीं ज्यादा निवेश करता है। यह सही है, लेकिन इसमें पेच है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टीवी बाजार है। 24 अरब डॉलर के मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग में टीवी और फिल्मों की हिस्सेदारी 56 फीसदी है। मनोरंजन पसंद करने वाले देश में यह आंकड़ा काफी छोटा है। आकार के लिहाज से डिज़्नी पूरे भारतीय मीडिया उद्योग से तीन गुना बड़ा है।ऐसे में भारतीय कहानियों की वैश्विक मांग से उद्योग को बेहतर मुद्रीकरण करने में मदद मिलेगा। समय भी अनुकूल है। पिछले दशक में इस दिशा में परिस्थितियां अनुकूल हुई हैं – डेटा के दाम घटे हैं, उपकरणों की संख्या बढ़ी है, वैश्विक फिल्मों और शो का चलन बढ़ा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय कथाकार पहले से कहीं बेहतर तरीके से तैयार हैं।

मीडिया पार्टनर्स एशिया का अनुमान है कि शीर्ष दस ओटीटी पर मौलिक, फिल्म सामग्रियों की मांग 2018 में 400 घंटे थी, जो 2019 में बढ़कर 1,000 घंटे हो गई है। यह 500 अतिरिक्त फिल्में बनाने के बराबर है जबकि पहले से ही देश में 1,600 फिल्में बनाई जा रही हैं। इसका मतलब है कि प्रतिभा, प्रसंस्करण, लेखन तथा अन्य सभी क्षेत्रों में अवसर बढ़ रहे हैं। अगर भारतीय कहानीकार इस क्षमता का इस्तेमाल करने में सक्षम होते हैं तो भारतीय मनोरंजन उद्योग अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन बन सकता है और सकल घरेलू उत्पाद में एक फीसदी से ज्यादा का योगदान दे सकता है। ईवाई का अनुमान है कि भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग 2021 तक 33 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।

आईआईटी दिल्ली की बौद्धिक संपदा फाइलिंग 20 प्रतिशत बढ़ी

विनय उमरजी
अहमदाबाद, 27 दिसंबर

पेटेंट और डिजाइन सहित बौद्धिक संपदा (आईपी) फाइलिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली में 2019 में पिछले साल की तुलना में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

आईआईटी दिल्ली ने 2019 में 150 आईपी फाइल कर न सिर्फ 2018 से बढ़त बनाई है, बल्कि यह अब तक का सर्वोच्च स्तर है। आईआईटी दिल्ली में इंडस्ट्री इंटरफेस ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशन फार इनोवेशन ऐंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (एफआईटीटी)ने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय दोनों पेटेंट दाखिल किए। आईआईटी दिल्ली के निदेशक रामगोपाल राव के मुताबिक आईपी लाइसेंसिंग से संस्थान की कमाई 4 गुना बढ़ी है। राव ने कहा, 'हम यह गति बरकरार रखने और देश में एक मानक तय करने की उम्मीद कर रहे हैं। तकनीक से जुड़े स्टार्टअप में विद्यार्थियों व फैकल्टी की भागीदारी बढ़ाने के लिए हमने कार्यक्रम की पहल की है।'

महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन से बुलेट ट्रेन पर नहीं लगा ब्रेक

सुशील मिश्र
मुंबई, 27 दिसंबर

महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होने के साथ बहुचर्चित बुलेट ट्रेन परियोजना में संकट के बदल मंडराने लगे थे। महाराष्ट्र सरकार ने इस परियोजना की समीक्षा करने के आदेश देकर अटकलों को और हवा दे दी कि भाजपा सरकार की महत्त्वाकांक्षी परियोजना पर ब्रेक लगाया जा सकता है। लेकिन मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने इन सभी अटकलों को खारिज करते हुए परियोजना के काम को आगे बढ़ने के लिए 1800 करोड़ रुपये की निविदा जारी की है।

नैशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन (एनएचआरसीएल) ने बीकेसी में बुलेट ट्रेन टर्मिनल के लिए तैयार करने के लिए 1800 करोड़ रुपये की निविदा निकाली है यह टर्मिनल 2023 तक बनकर तैयार हो जाना है।

बुलेट ट्रेन पर चल रही चर्चा पर एमएमआरडीए के अध्यक्ष आर ए राजीव ने कहा कि सत्ता परिवर्तन से परियोजना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होने कहा कि इस परियोजना से भारी संख्या में रोजगार पैदा होगे। निवेशकों से कई तरह के करार किए जा चुके हैं इससे आगे भी और निवेशक आएगे। उन्होने कहा कि गुजरात की तुलना में महाराष्ट्र को बुलेट ट्रेन से कम फायदा होगा इस तरह के आरोप किये जा रहे हैं, किसानों को कर्जमाफी के लिए बड़ी रकम की जरूरत है इसीलिए इस परियोजना को टाला जा सकता है ऐसी चर्चा हो रही है जिन पर अब विराम लगना चाहिए। बीकेसी में बनने वाला टर्मिनस भूमिगत तैयार किया जाएगा। इस टर्मिनल के ऊपर आईएफएससी की 96 मीटर ऊंची इमारत तैयार की जाएगी। इसके लिए एमएमआरडीए ने निविदा जारी की है। इमारतों के लिए 50 हेक्टेयर जमीन मंजूर की गई है। इसमें से 5.9 हेक्टेयर में भूमिगत बीकेसी टर्मिनल तैयार किया जाएगा। इस टर्मिनस से एक साथ छह गाड़ियां निकल सकेगी। यह टर्मिनस 16 डिब्बे वाली बुलेट ट्रेन के खड़ी होने के लिए 460 मीटर लम्बा होगा। 2020 के मध्य से निर्माण काम शुरु हो जाएगा और अगले दो सालों में यह आधुनिक सुविधाओं वाला यह टर्मिनल तैयार हो जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुलेट ट्रेन की समीक्षा करने का आदेश दिया था जिसके बाद यह कयास लगाये जा रहे थे कि शिवसेना अपने सहयोगी दलों के दबाब में इस परियोजना को रोक सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अफवाहों पर विराम लगाने के लिए स्पष्ट किया था कि किसी भी परियोजना पर रोक नहीं लगाई गई है।

बीएस सूडोकू 3624 | परिणाम संख्या 3623

2				5	6		1	9
4							7	
5						8		
	6		9			1	5	
			6		7			
	3	1			5		2	
		5						7
	4							1
1	7		4	6				3

3	4	7	2	6	1	5	9	8
2	9	1	8	3	5	4	6	7
5	8	6	9	4	7	2	1	3
9	7	2	1	8	4	6	3	5
8	1	3	7	5	6	9	4	2
4	6	5	3	2	9	8	7	1
7	5	9	6	1	2	3	8	4
6	2	8	4	7	3	1	5	9
1	3	4	5	9	8	7	2	6

कैसे खेलें?

हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

मुश्किल ★★★★☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2165/2175, जौ 1770/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2200/2250, सरसों 4575/4600, तिल सफेद 9500/9700, सोया (टीन) 1575/1625, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1650/1700,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2175/2185, गेहूं शरबती 2900/3000, चावल शरबती सेला 3700/3750, स्टीम 4200/4300, लालमती 3300/3400, चावल (सोना) 2950/3000

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1450, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1530, फ्लैक 1470, डीएमओ 1065, टरपीन लैस बोल्ड 1560

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1200/1315, खुरपा 1200/1230,चाकू 1150/1295, रसकट 920/935, शक्कर 1360/1390, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली3385, सिहोरा 3255, बुंदकी 3290, बुढ़ाना 3370,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3550/3650, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 1200/1230, तिलहनः सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4650, खलः सरसों 2350/2450, बिनौला 2550/2700, चना छिलका 2050/2150,

जयपुर
अनाजः चावल डीबी 5600/5700, गेहूं (मिल) 2200/2210, मक्की 2250/2275, बाजरा 1920/1925, जौ 1800/1825, ग्वार लूज 3800/3850, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, तेल-तिलहनः सरसों(मिल पहुंच) 4820/4825,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2075/2125, ग्वार 3800/3850, जौ 2080/2090,

जोधपुर
गेहूं 2075/2100, जौ 1750/1775, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4100/4150, ग्वारगम 7600/7700, बाजरा (गुजरात) 1990/2000, बाजरा (जयपुर) 2000/2010, चना 4250/4350, काबली चना 5000/6000, मूंग 6500/6600,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)131, राइसब्रान (अखाद्य) 128, खल सरसों 2100, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1300, लाल 1300, कंटीन्यूअस 1350,

लुधियाना
दाल-दलहनः राजमां चित्रा 7200/8200, अरहर दाल 7500/8000, उड़द साबुत 7650/8600, उड़द धोया 9000/10000, छिलका 8500/9500, दाल मसूर 5800/6200, चनादाल 5300/5600,

अमृतसर
चावलः बासमती (1121 नं.) स्टीम 6100/6200, सेला 5550/5600, शरबती साधारण सेला 3750/3850, शरबती स्टीम 4150/4250,चावल 1509 सेला 5150/5250, धानः शरबती 2100/2150,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 4020/4050, हरियाणा 4000/4025, राजस्थान 3960/4020, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2600/2700, सरसों खल 2240/2250,

फाजिल्का
गेहूं 2230/2240, सरसों 4525/4550 रुई (प्रति मन): (जे-34) 4050/4100, कपास देशी 5050/5150, कपास नरमा (क्विं.) 5350/5500, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2600/2700,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2225/2235, चावल परमल कच्चा 2500/2550, से ला 2400/2425, मक्की यूपी 2375/2400, बिहार 2475/2500, दाल उड़द छिलका 9000/10700, चना देशी 5150/5250, दाल चना 5400/5600, काबली चना 5100/6000, राजमां चित्रा पुणे 7000/8400, चीन 7500/8100,

करनाल
गेहूं दड़ा 2210/2230, बासमती चावल 6500/6600, धान 1121 नं. 2900/2925, पूसा 1509 धान 2600/2650, शरबती धान 2150/2200, सेला (1509 नं.) चावल 5200/5300, स्टीम 6000/6100,

हिसार
ग्वार 3825/3850, जौ 1775/1780, सरसों 4250/4300, मूंग 6500/6600, गेहूं 2140/2150,

जींद
जीएसटी अतिरिक्तः गेहूं 2100/2150, आटा (प्रति 44 किलो) 1050/1070, मैदा 1150/1170, देशी घी (एक ली/जार) 380/480, रिफाइंड (टीन) 1510/1540,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्तः सरसों 4300/4350, खल बिनौला मोटी 2500/2600, बिनौला 2900/3400, सरसों तेल 9450/9500, गेहूं 2150/2200, ग्वार 3850/3900, बाजरा 1950/2000 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 268

वास्तविक हो बजट

बजट की रूपरेखा तैयार करते वक्त किसी भी वित्त मंत्री को सबसे पहले आगामी वर्ष में अर्थव्यवस्था की संभावित वृद्धि दर तय करनी होती है। राजस्व, घाटा तथा तमाम अन्य आंकड़े इस बात पर निर्भर करते हैं कि सरकार उक्त वृद्धि दर का कितना सटीक आकलन लगा पाती है। उदाहरण के लिए चालू वर्ष में यदि मुद्रास्फीति समेत जीडीपी वृद्धि दर (नॉमिनल) का अनुमान सही होता तो राजस्व आकलन में कुछ गंभीर खामियों से बचा जा सकता था।

सही अनुमान अतीत के रुझानों के सही अध्ययन पर निर्भर करता है। सन 2020 तक के दशक में अर्थव्यवस्था कमोबेश दोगुनी हो गई। इस दौरान औसत वृद्धि दर 7 फीसदी की रही। परंतु दशक के बीच के वर्षों में अर्थव्यवस्था को तेल कीमतों में भारी गिरावट से भी लाभ मिला। यह शायद दोहराया न जाए। इसके अलावा मौजूदा वैश्विक आर्थिक हालात भी बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं हैं। घरेलू अर्थव्यवस्था में कई सुधार करने की आवश्यकता है। वित्तीय क्षेत्र में सुधार की जरूरत है, निर्यात में ठहराव है, राजकोषीय या मौद्रिक नीति पहल की कोई खास गुंजाइश नहीं है। बीती तिमाही में चूंकि अर्थव्यवस्था का गैर सरकारी हिस्सा 3 फीसदी की गति से ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ा, ऐसे में अर्थव्यवस्था के लिए अगले वर्ष के लिए 5 फीसदी के आसपास की अनुमानित वृद्धि दर ही वास्तविक होगी। इसमें ज्यादा से ज्यादा आधा फीसदी का बदलाव हो सकता है।

बीते दशक में 7 फीसदी की वृद्धि हासिल करने वाली तथा उससे पिछले दशक में और तेजी हासिल करने वाली अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत अच्छी दर नहीं है। परंतु हमारे सामने जिस तरह के कठिन विकल्प हैं, उन्हें देखते हुए धीमी वृद्धि को स्वीकार करने के सिवा चारा नहीं है। फिलवक्त तो 7 फीसदी की दर से विकसित होती अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राजस्व अनुमान लगाया भी नहीं जा सकता। ऐसे में हकीकत का सामना करना ही बेहतर है। खासतौर पर तब जबकि बात बजट की तैयारी की हो। बजट में घाटे के आंकड़े को काफी कम करके बताया गया है। यह कमी जीडीपी के 2 फीसदी तक है। हर बजट में संसाधनों की सीमा होती है लेकिन आने वाले बजट में यह संकट भी चरम पर होगा।

साप्ताहिक मंथन
टी. एन. नाइनन

बजट से इतर देखें तो मध्यम अवधि में पूर्वानुमान काफी उलझाऊ है। खासकर तब जबकि वृद्धि दर को 7 फीसदी के वांछित स्तर पर लौटने में समय लगे। वित्त मंत्री को अपने बजट भाषण में यह साफ करना चाहिए कि वह 7 फीसदी की दर कैसे हासिल करेंगी। उन्हें धीमी होती अर्थव्यवस्था के गतिशील होने तक हकीकत को अपनाने के लिए वह क्या कदम उठाने जा रही हैं उनके बारे में भी उन्हें सूचित करना चाहिए। सरकारी कदमों के बारे में अनुमान लगाया जा सके तो यह हमेशा बेहतर होता है।

राजस्व में कमी होने पर तलवार व्यय पर गिरेगी, भले ही मंदी के मध्य अर्थशास्त्री ऐसी सलाह नहीं दें। यह बात अहम है कि बजट अनुशासन नजर आए। ऐसे में आवंटन को मौजूदा स्तर पर बरकरार रखना होगा। जो पैसा व्यय न हो वह समाप्त हो जाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में बहुत अधिक सार्वजनिक निवेश हो चुका है, उनसे कहा जाना चाहिए कि वे प्रदर्शन में सुधार दर्शाएं। उदाहरण के लिए रेलवे का राजस्व, राजमार्ग टोल, उच्च बिजली टैरिफ आदि। यदि वित्त मंत्री कड़ी निगाह डालें तो उन्हें और अधिक गैर कर राजस्व की राह निकालने में आसानी होगी। उदाहरण के लिए सरकारी बैंकों के लिए नई पूंजी जुटाने के लिए उनमें से एक या दो का निजीकरण कर दिया जाना चाहिए। इसका बोझ करदाताओं पर नहीं डालना चाहिए।

सबसे बढ़कर बजट को आधुनिक बनाने का वक्त आ गया है। सबसे पहले नकद अंकेक्षण से संग्रहण अंकेक्षण की ओर बढ़ना चाहिए ताकि उन बिलों को शामिल किया जा सके जो बकाया हैं लेकिन चुकता नहीं हैं। इसी प्रकार सरकार को बैलेंस शीट से इतर मुद्दों की जानकारी देनी चाहिए जो अब तक बजट का हिस्सा नहीं हैं। इसे ऐसी खबरें आनी बंद होंगी जिनमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा छिपे हुए व्यय पर सवाल उठाया जाता है। मिसाल के तौर पर सरकारी कंपनियों द्वारा बैंकों से पैसे उधार लेकर खाद्य सब्सिडी बिल चुकाना या रेलवे संस्थानों से अग्रिम भुगतान लेना ताकि रेलवे के खाते में घाटा न दिखे। अधिक विश्वसनीय आंकड़े बेहतर होंगे और इससे सरकारी कामकाज की पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

बिनय सिन्हा

वित्तीय मजबूती की राह पर चीन निरंतर अग्रसर

विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला चीन मुद्रा के क्षेत्र में कई ऐसे कदम उठा रहा है जिनसे लगता है कि भविष्य उसके ही नाम होगा। विस्तार से बता रहे हैं **श्याम सरन**

चीन जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। फिलहाल उसकी अर्थव्यवस्था का आकार 14 लाख करोड़ डॉलर है, जो विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब 18 प्रतिशत है। वर्ष 2013 से यह दुनिया का सबसे बड़ा कारोबारी देश रहा है और इसका मौजूदा आयात-निर्यात का कुल आंकड़ा 4.5 लाख करोड़ डॉलर से अधिक है। इतना ही नहीं, चीन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शेयर एवं बॉन्ड बाजार भी है। इसका बॉन्ड बाजार 13 लाख डॉलर का है और दुनिया के बॉन्ड बाजार में इसकी हिस्सेदारी 14 प्रतिशत है। इसी तरह, इसका शेयर बाजार पूंजीकरण वैश्विक आंकड़े का करीब 12 प्रतिशत है। हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन का रुतबा इसके वित्तीय आंकड़ों में नहीं झलकता है।

वैश्विक स्तर पर लेनदेन के माध्यम के रूप में चीन की मुद्रा की हिस्सेदारी 2018 में कम होकर 15 प्रतिशत से कम रह गई है, जबकि 2013 में यह आंकड़ा 25 प्रतिशत तक हुआ करता था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुल भुगतान में केवल 2 प्रतिशत ही रेनमिनबी के जरिये होता है। 2016 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के लाख करोड़ डॉलर मूल्य के स्पेशल ड्रॉइंग राइट (एसडीआर) में अमेरिकी डॉलर, यूरोपीय क्षेत्र की मुद्रा यूरो, जापानी मुद्रा येन और ब्रिटेन के पाउंड के साथ रेनमिनबी भी सुरक्षित मुद्रा के रूप में शामिल थी। रेनमिनबी का भारांश एसडीआर में 10.86 प्रतिशत दिया गया था। आईएमएफ के सदस्य देशों के विदेशी मुद्रा भंडार में रेनमिनबी की मात्रा अधिकतम 1 लाख डॉलर तक हो सकती है, लेकिन फिलहाल यह महज 194 अरब डॉलर ही है। चीन ने 30 देशों के साथ मुद्रा अदला-बदली (करेंसी स्वैप) का समझौता कर रखा है और इसका मूल्यांकन फिलहाल 500 अरब डॉलर है। हालांकि इसका इस्तेमाल मामूली स्तर तक ही हुआ है। रेनमिनबी दुनिया की दूसरी शीर्ष मुद्राओं की तरह विश्वसनीयता अर्जित करने में असफल रही है। पूंजी प्रवाह पर नियंत्रण समाप्त करने और मुद्रा में उतार-चढ़ाव झेलने से चीन के इनकार करने से आगे की प्रगति अब तक थमी है।

युआन के अंतरराष्ट्रीयकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चीन ने अब एक अलग रणनीति तैयार की है। अपनी मुद्रा को अपेक्षित स्थान दिलाने के लिए चीन अपने बॉन्ड एवं शेयर बाजार के बड़े आकार का इस्तेमाल करते हुए इन्हें वैश्विक वित्तीय बाजारों से जोड़ रहा है। शुरू में चीन ने अपने शेयरों में कोटा आधारित कारोबार की अनुमति देने के लिए हॉन्ग कॉन्ग, शांघाई और हॉन्ग कॉन्ग शेनझेन स्टॉक कनेक्ट स्थापित किया और कोटा को उदार बनाया और फंडों के स्थानांतरण की प्रक्रिया सरल बना दी। इसने अपना बॉन्ड बाजार विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की और पहले रेनमिनबी में जारी बॉन्ड हॉन्ग कॉन्ग और बाद में सिंगापुर, ताइवान और लंदन में उतारे।

प्रमुख वैश्विक सूचकांकों में चीन के शेयर एवं बॉन्ड को शामिल किया जाना उत्साहजनक है। शांघाई एवं शेनझेन स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार करने वाले चीन के ए-शेयर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट और एमएसएसीआई ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स में शामिल किए गए हैं। चाइनीज गवर्नमेंट बॉन्ड (सीजीबी) अब ब्लूमबर्ग बार्कलेज ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में शामिल हैं और जल्द ही एफटीएसई का हिस्सा हो सकते हैं। निवेश कंपनी स्क्रोडर्स का दावा है कि आम तौर पर सूचकांकों से जुड़े फंडों में निवेश करने वाले अंतरराष्ट्रीय संस्थागत निवेशक से रकम का प्रवाह शुरू में सालाना 200 अरब डॉलर होगा, जो बाद में बढ़कर सालाना 400 अरब डॉलर तक हो जाएगा।

चीन के शेयर एवं बॉन्ड बाजारों का तेजी से विस्तार हो रहा है और खुदरा निवेशकों ने भी इनमें बढ़-चढ़ कर निवेश शुरू कर दिया है, ऐसे में रकम का प्रवाह लाखों करोड़ों डॉलर में रह सकता है। यह ध्यान रहे कि केवल सीजीबी ही अब तक शामिल किए गए हैं। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड के शामिल होने में भी अधिक देर नहीं है। स्टैंडर्ड ऐंड पुअर्स को चीन में रेटिंग एजेंसी के तौर पर काम करने की अनुमति मिल चुकी है। अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों के लिहाज से कॉर्पोरेट बॉन्ड को रेटिंग मिलने से उनके लिए वैश्विक सूचकांकों में शामिल होना आसान हो जाएगा और इससे चीन के बॉन्ड बाजार में रकम का प्रवाह भी बढ़ेगा। शांघाई में युआन आधारित तेल वायदा एक्सचेंज की स्थापना से भी चीन की मुद्रा की हैसियत बढ़ रही है। शांघाई इस साल दुबई को पछाड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल वायदा बाजार बन गया है।

चीन के यूनियनपे क्रेडिट कार्ड का अंतरराष्ट्रीय वित्त बाजार में रुतबा बढ़ा रहा है। दुनिया में जारी कुल क्रेडिट कार्ड में यूनियनपे की हिस्सेदारी 58 प्रतिशत है और इस समय करीब 7.6 अरब यूनियनपे क्रेडिट कार्ड धारक हैं। यह क्रेडिट कार्ड 174 देशों में स्वीकार होता है। हरेक साल चीन के लोग 15 करोड़ विदेशी यात्राएं करते हैं और पर्यटन पर हरेक साल होने वाले कुल खर्च में इनका हिस्सा 20 प्रतिशत है। इस वजह से दुनिया के कारोबारी प्रतिष्ठान यूनियनपे क्रेडिट कार्ड से भुगतान ले रहे हैं।

चीन ने 2015 में क्रॉस-बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम (सीआईपीएस) शुरू किया था, जो ब्रसल्स स्थित स्विफ्ट की तर्ज तैयार किया गया है। इस समय सीआईपीएस स्विफ्ट के साथ सहयोग कर रहा है, लेकिन चीन का वास्तविक लक्ष्य एक वैकल्पिक वैश्विक भुगतान एवं निपटान प्रणाली के तौर पर इसे (सीआईपीएस) स्थापित करना है। सीआईपीएस में 12 अंतरराष्ट्रीय बैंकों के साथ 31 साझेदार हैं, इसके साथ ही 745 परोक्ष रूप से इसमें भागीदार निभाते हैं। 2018 में सीआईपीएस ने चीन से बाहर युआन में 755 अरब डॉलर के लेनदेन का निपटान किया। हालांकि स्विफ्ट के मुकाबले यह न के बराबर है, लेकिन इसके जरिये निपटान तेजी से बढ़ रहा है। स्विफ्ट प्रतिदिन 6 लाख करोड़ डॉलर का निपटान करता है। सीआईपीएस के इस्तेमाल को अमेरिका के कदमों से भी बढ़ावा मिला रहा है, जो रूस और ईरान जैसे देशों को बाहर रखने के लिए स्विफ्ट का इस्तेमाल करता है। रूस ने अपना सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मेसेजेज स्थापित किया है, जो यूरेशियन इकनॉमिक यूनियन देशों में काम करती है और चीन के बैंक इसमें शिरकत करते हैं। ऐसी खबर आ रही है कि अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए भारत, चीन और रूस त्रिपक्षीय भुगतान प्रणाली विकसित करने पर विचार कर रहे हैं, जो स्विफ्ट से स्वतंत्र होकर काम करेगी।

चीन ब्लॉकचेन तकनीक आधारित संप्रभु डिजिटल करेंसी लाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि इस बारे में अभी विस्तार से कोई सूचना नहीं है। चीन में इस समय होने वाले कुल लेनदेन में 70 प्रतिशत से अधिक डिजिटल माध्यम से होते हैं, इसलिए सॉवरिन डिजिटल करेंसी की दिशा में काम करना कोई हैरत की बात नहीं। एक 'एशियाई युआन' बनाने के लिए इसे एक दूसरी समानांतर योजना से जोड़ा जा रहा है। चीन के अर्थशास्त्री सन मिन्गाकी इस रणनीति का खुलासा कुछ इस तरह करते हैं, 'हॉन्ग कॉन्ग डॉलर और न्यू ताइवान डॉलर को आंतरिक स्तर पर जोड़कर 'ग्रेटर चाइना रेनमिनिबी तैयार करना लघु अवधि का लक्ष्य है। मध्यम अवधि में जापान की येन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के वोन और दूसरी एशियाई देशों की मुद्रा के सहयोग से 'एशियाई युआन' प्रणाली अस्तित्व में लाने का लक्ष्य है। इससे अमेरिकी डॉलर, यूरो और एशियाई युआन वैश्विक मुद्रा प्रणाली के तहत त्रिकोणीय व्यवस्था के रूप में काम करेगी।' कुल मिलाकर अंतिम लक्ष्य प्रत्येक देश की आर्थिक ताकत एवं उसके कारोबार मूल्यांकन के आधार पर एक आदर्श, डिजिटल एवं विकेंद्रीकृत या गैर-सॉवरिन वैश्विक मुद्रा प्रणाली स्थापित करना है। अब सवाल उठता है कि अगर चीन ने डिजिटल करेंसी के साथ कदम आगे बढ़ा दिए हैं तो यह लक्ष्य प्राप्त होने के बाद भविष्य किसके नाम होगा? इन घटनाक्रम के बीच भारत कहां खड़ा होता है, जो इस समय अपनी कुछ परेशानियों से जूझ रहा है?

(लेखक पूर्व विदेश सचिव और सीपीआर में सीनियर फेलो हैं।)

दलित उत्थान के लिए चंद्रशेखर आजाद से 'रावण' तक का सफर

सियासी हलचल
आदिति फडणीस

इस बात में थोड़ा आश्चर्य हो सकता है कि मायावती और अन्य लोग उनके नाम का उल्लेख करने पर भौंह सिकोड़ लेते हैं। हालिया आंदोलन ने रावण की शख्सियत को मजबूत किया है

जिस समय दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के खिलाफ आवाज उठ रही थी तो एक व्यक्ति पुलिस के साथ लुकाछिपी का खेल खेल रहा था। खुद को रावण नाम देने वाले चंद्रशेखर भी यह लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका जन्म सहारनपुर के धड़कूलि गांव में एक चमार परिवार में हुआ था। चंद्रशेखर ने पास के ही छुटमलपुर गांव में ठाकुरों द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल से पढ़ाई की। उन्होंने दलितों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को महसूस किया और इससे लड़ने की ठानी। आंबेडकरवादी और कांशी राम से प्रभावित (लेकिन मायावती की तरह नहीं) चंद्रशेखर ने दलितों को संगठित करने के लिए कांशी राम के आदर्शों पर चलने का प्रयास किया। उन्होंने शिक्षा, अफसरशाही और आत्मरक्षा के तरीके आजमाए। उन्होंने भीम आर्मी का गठन किया और जाति तथा महिला-पुरुष के भेदभाव से परे सभी को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा देने के लिए सहारनपुर जिले में 400 भीम आर्मी स्कूल खोले। उन्होंने आत्मरक्षा की कक्षाएं चलाना शुरू किया और गांवों में घूम-घूम कर बाइक रैलियां कीं। इन गांवों में ऊंची जाति वाले ठाकुरों के गांव भी शामिल थे। वे इसे अपने मजबूत होते वजूद को दिखाने के सांकेतिक तरीके के तौर पर देखते थे।

यह काफी जरूरी है। लोध जाति से ताल्लुक रखने वाली और बाद में केंद्रीय मंत्री बनीं साध्वी उमा भारती एक पुरानी घटना के बारे में बताती हैं कि उनके गांव टीकमपुर में उनकी जाति के दूसरे लोग ठाकुर परिवारों के घरों के आगे से साइकिल चलाकर नहीं जा सकते थे। उन्हें साइकिल से उतरकर पैदल चलना होता था क्योंकि ठाकुर इसे अपना अपमान मानते थे। यह 25 साल पहले की बात है। हालांकि आज भी कुछ नहीं बदला। भीम आर्मी ने 18 साल से अधिक उम्र के दलितों को संगठन से जुड़ने का आह्वान किया। इसके ज्यादातर सदस्य चमार समुदाय या इसकी उपजाति जाटव से संबंधित हैं। लेकिन भीम आर्मी ने मुसलमानों का भी समर्थन किया। हालांकि संगठन का किसी तरह का औपचारिक ढांचा नहीं है और यह गैर-पंजीकृत संस्था है लेकिन दावा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में इसके 20,000 से ज्यादा सदस्य हैं। संगठन का ज्यादातर ध्यान प्रत्यक्ष तरीके से मदद करके दलितों की गरिमा का संरक्षण और उसका बचाव करना है। हाल ही में दिए एक साक्षात्कार में आजाद ने कहा, 'भीम आर्मी की मदद से दलित युवाओं को पता चला कि वे अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और वे अब उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। भीम आर्मी किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि दलितों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है।'

साल 2015 में उस समय रावण की परेशानी शुरू होने लगी जब उन्होंने अपने गांव के बाहर एक बोर्ड लगाया। इसमें लिखा था, 'धड़कूलि गांव के चमार आपका स्वागत करते हैं।' जिस गांव में ठाकुर रहते हों वे इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? ठाकुरों ने इस पर काली स्याही पोत दी। अब यह तनाव सीधी लड़ाई में तब्दील हो गया और उस दौरान शीर्ष पर पहुंच गया जब भाजपा ने बिना मंजूरी लिए सहारनपुर के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाके में 'शोभा यात्रा' निकाली। कुछ सप्ताह बाद राजपूत राजा महाराणा प्रताप की जयंती पर दलित-ठाकुर टकराव हो गया। राज्य सरकार ने हिंसा भड़काने के लिए भीम आर्मी को जिम्मेदार ठहराया। रावण ने दावा किया कि सरकार इस आंदोलन को दबाने और ऊंची जाति के लोगों को संरक्षण देने के लिए उन्हें निशाना बना रही थी। राज्य प्रशासन ने रावण को गिरफ्तार कर लिया। मामला न्यायालय में पहुंचा और उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया। हालांकि कुछ घंटे बाद ही योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उनको दोबारा गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले समूहों के भारी विरोध के बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया था लेकिन इस दबाव के चलते उन्हें रिहा कर दिया गया। जब वह जेल (और अस्पताल) में थे तो प्रियंका गांधी ने टेलीफोन पर बात की थी। आजाद अघोषित तौर पर कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने लगे।

सहारनपुर दलितों के लिए आवाज उठाने और मुसलमानों तथा दलितों के बीच एकता के लिए जाना जाता है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पहल का समर्थन किया। लोकप्रिय लेखक और दलित चिंतक चंद्रभान प्रसाद के अनुसार, 'करीब 400 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दलित और मुस्लिम कुल मतदाताओं के 30 प्रतिशत हैं। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि 90-95 प्रतिशत दलित और मुसलमान घरों से बाहर निकलकर मतदान करते हैं। इसलिए अगर वे साथ आते हैं तो चुनाव की दृष्टि से अहम हो जाएंगे। मेरा मानना है कि दलितों और मुसलमानों, खासकर युवाओं में एक साथ आने को लेकर काफी उत्सुकता है।' रावण इस एकता का चेहरा बनकर उभरे हैं हालांकि देश के दूसरे हिस्सों में अधिक लोग उन्हें नहीं जानते। जिस दौर में बसपा की चुनावी जमीन लगभग समाप्त हो गई हो और भाजपा दलितों को लामबंद करने में जुटी हो, ऐसे में भीम आर्मी दलित समुदाय में से प्रतिरोध का प्रतीक बनकर उभरी है। प्रख्यात दलित विद्वान आनंद तेलतुम्बडे लिखते हैं कि इसकी उत्पत्ति को वर्ष 1972 में महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स से जोड़कर देखा जा सकता है जो भारत की तत्कालीन दिवालिया राजनीति का नतीजा था।

इस बात में थोड़ा आश्चर्य हो सकता है कि मायावती और अन्य लोग उनके नाम का उल्लेख करने पर भौंह सिकोड़ लेते हैं। हालिया आंदोलन ने रावण की शख्सियत को मजबूत किया है।

कानाफूसी

समांतर मार्च

कोलकाता में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अध्यापक ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के विरोध में आयोजित रैली में हिस्सा लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग के डीन प्रदीप बसु एनआरसी और सीएए की कॉपी जलाने के नारे लगा रहे हैं। उन्हें फासीवादी सरकार को हटाने की बात कहते हुए भी सुना जा सकता है। बसु ने कहा कि प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय से श्याम बाजार तक चार किलोमीटर लंबा यह मार्च स्वत: स्फूर्त था और किसी राजनीतिक दल या छात्र संगठन का झंडा देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि विरोध करने की जरूरत महसूस हो रही थी और छात्रों ने संपर्क किया तो वह तैयार हो गए।

मशविरों का दौर

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सन 2020 के बजट को लेकर आंतरिक मशविरे की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। पार्टी की कोशिश यह है कि वह बजट निर्माण के पहले सभी संबद्ध लोगों से संपर्क करे और उस बातचीत से निकला फीडबैक मोदी सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दे। पार्टी ने इस कवायद का जिम्मा संगठन महासचिव बी एल संतोष को सौंपा है। पार्टी के आर्थिक मामलों के प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल ने पिछले दिनों कहा कि ऐसे हर सुझाव का स्वागत है जो पार्टी और सरकार को जमीनी हकीकतों से रूबरू कराए। मशविरे की प्रक्रिया गत 19 दिसंबर को आरंभ हुई और यह 14 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में 11 चर्चाओं का आयोजन किया जाएगा। इन मशविरों की रिपोर्ट को भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा से चर्चा के बाद सरकार को भेज दिया जाएगा।

आपका पक्ष

जैविक खेती को मिले बढ़ावा

फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक से खेती करना जरूरी है, क्योंकि इससे किसानों को ज्यादा फायदा हो सकता है। देश के किसान अब आधुनिक तकनीक से खेती करने लगे हैं। अगर विज्ञान का उचित प्रयोग किया जाए तो मनुष्य के लिए यह वरदान साबित हो सकती है लेकिन इसके अनुचित प्रयोग से अभिशाप भी बन सकती है। कुछ किसान फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी फसल को जब कोई किसी रूप में सेवन करता है तब उस पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फल, सब्जियों की पैदावार या इसके भंडारण में जिन रसायन का इस्तेमाल किया जा रहा है वे भी शरीर के लिए हानिकारक है। ये जानलेवा बीमारियों को बढ़ावा देने में योगदान दे रहे। अगर

समय रहते रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक खाद का प्रयोग नहीं किया गया तो अनाज सेहत का दुश्मन बन जाएगा। जैविक खाद का प्रयोग बढ़ाने के लिए सरकार को विशेष योजनाएं लाने के साथ किसानों को तकनीकी मदद देनी होगी। किसानों को पशुपालन के

खेतों में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल पर सरकार को रोक लगानी चाहिए

प्रति जागरूकता के लिए नई नीति बनानी चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

गरीबों की पहुंच से दूर होता प्याज

प्याज एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसका उपयोग सामान्य लोग करते हैं। यह खासकर गरीबों के लिए एक सब्जी की तरह है जिससे वे रोटी के साथ खा लेते हैं। पिछले महीनों में प्याज के दाम बेतहाशा बढ़े हैं और यह गरीब की पहुंच से बाहर हो चुका है। प्याज के दाम में कमी लाने के लिए सरकार विदेशों से इसका आयात कर रही है जिसकी कीमत 50 प्रतिशत से अधिक है। ऐसे में प्याज की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिससे इसकी कीमतों में कमी आ सके।

घेवरचंद गोदीका, जयपुर

मांग आपूर्ति में संतुलन हो

वस्तु हो या सेवा अगर मांग और आपूर्ति के असंतुलन को समझ कर कारोबार करें तो यह सभी के हित में होगा। इससे रोजगार की कमी नहीं होगी और न ही उत्पादित वस्तुओं की बिक्री में कमी आएगी। जहां मांग और आपूर्ति का आकलन नहीं किया गया वहां कारोबारी संकट में आ जाते हैं। उन्हें या तो इन्वेंट्री की समस्या घेरती है या फिर उन्हें आपूर्ति की समस्या से जूझना पड़ता है। अगर रेलवे की सवारी डिब्बों की बात करें तो पता चलेगा कि वह अत्यधिक है। एसी डिब्बों की मांग इतनी है कि अगले कुछ साल तीन शिफ्ट में निर्माण कार्य चलाया जाए फिर भी पूरी नहीं होगी। आगामी बजट में सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि रोजगार सृजन हो सके।

हिम्मत जोशी, नागपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

आयातित प्याज आया लेकिन दाम नहीं घटे

प्याज की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आयात बढ़ाने के बावजूद इसकी खुदरा कीमतें शुक्रवार को बढ़कर 150 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई। यह कीमत तब पहुंची है जब आयातित प्याज की खेप की आवक शुरू हो गई है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, महानगरों में से कोलकाता में प्याज का खुदरा मूल्य 120 रुपये किलो, दिल्ली और मुंबई में 102 रुपये किलो तथा चेन्नई में 80 रुपये किलो है। ज्यादातर शहरों में प्याज की कीमतें 100 रुपये किलो थी। ईटानगर में प्याज की कीमत 150 रुपये किलो पर पहुंच गई। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'आयातित प्याज की आवक शुरू हो गई है। लगभग 1,160 टन प्याज भारत पहुंच चुका है। अगले 3 से 4 दिनों में अतिरिक्त 10,560 टन आयात की खेप आने की उम्मीद है।' अधिकारी ने कहा कि लाल और पीले दोनों किस्म के प्याज तुर्की, मिस्र और अफगानिस्तान से आयात किए गए हैं। आयात की ये खेपें मुंबई बंदरगाह पर उतरती हैं। सरकार की ओर से प्याज का आयात करने वाली सरकारी स्वामित्व वाली एमएमटीसी ने अब तक 49,500 टन प्याज का अनुबंध किया है। अगले महीने कुछ आयातित खेप आएंगी। प्याज के प्रमुख उत्पादक राज्यों में अत्यधिक बारिश के कारण पिछले वर्ष की तुलना में फसल वर्ष 2019-20 (जुलाई-जून) में खरीफ उत्पादन में 25 प्रतिशत की गिरावट की आशंका के बाद प्याज कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। पिछले कुछ हफ्तों में कई सरकारी उपायों के बावजूद कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। सरकार ने पहले ही प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। व्यापारियों पर स्टॉक रखने की सीमा लागू कर दी है और बफर स्टॉक से सस्ती दर पर प्याज की आपूर्ति भी की जा रही है।

व्यापारियों और विशेषज्ञों का मानना है कि प्याज की कीमतें जनवरी तक बढ़ी रहेंगी। जब तक देर से तैयार होने वाले खरीफ फसल बाजार में आना शुरू नहीं हो जाए तबतक कीमतों में नरमी की संभावना नहीं है। इससे पहले भारत ने आखिरी बार वर्ष 2015-16 में 1,987 टन प्याज का आयात किया था जब इसकी कीमतें काफी बढ़ गई थीं। *भाषा*

टिड्डी हमला, मिलेगा मुआवजा

चार जिलों के 124 गांवों में फसल तबाह, सरकार करा रही कीटनाशक छिड़काव

विनय उमरजी
अहमदाबाद, 27 दिसंबर

- **पाकिस्तान के रास्ते घुसा टिड्डी दल, रबी फसल प्रभावित**
- **राज्य ने तैनात कीं 100 टीमें, इनमें 16 टीम केंद्र सरकार ने भेजीं**

गुजरात सरकार ने उत्तर गुजरात में टिड्डों के हमलों से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। राज्य सरकार ने आज कहा कि प्रभावित इलाकों के 25 प्रतिशत हिस्से में कीटनाशकों के छिड़काव से टिड्डे मर गए हैं। गुजरात सरकार के कृषि, किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पूनमचंद परमार के मुताबिक राज्य सरकार ने टिड्डों के खतरे से निपटने के लिए स्प्रे मशीन और ट्रैक्टर से लैस 100 टीमें बनाई हैं जिसमें 16 टीम केंद्र सरकार की हैं।

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने उत्तर गुजरात इलाके के पीड़ित किसानों को मुआवजे का आश्वासन दिया और दिन में बिजली आने की किसानों की मांग पर भी काम करने का आश्वासन दिया है। किसानों ने पानी के पंप चलाने और टिड्डियों को भगाने के लिए तेज संगीत बजाने के लिए दिन के समय में भी बिजली देने की मांग की थी। परमार के अनुसार, चार जिलों के 17 तालुका में बसे 124 गांवों में टिड्डों की स्थिति गंभीर स्तर पर है। इनमें बनासकांठा जिले के 13 तालुकाओं के 114 गांव, मेहसाणा के एक तालुका के पांच गांव, पाटन जिले के दो तालुका के चार गांव और साबरकांठा जिले के एक तालुका का एक गांव शामिल हैं। इससे पहले, उत्तर गुजरात के कई हिस्सों में टिड्डों के हमले में अरंडी, जीरा और सरसों जैसी फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसे दो दशकों में टिड्डों के सबसे बड़े हमले के तौर पर माना जा रहा है। उत्तर गुजरात क्षेत्र के किसानों के अनुसार बनासकांठा में कीटों के हमले का ज्यादा प्रभाव देखा गया है। वहां कीटों के हमले से 25-30 प्रतिशत खड़ी फसल खराब हो गई है। हालांकि नुकसान के आधिकारिक आंकड़े का अभी इंतजार किया जा रहा है।

भारत किसान संघ (बीकेएस) के सदस्य (पशुपालन) कुराभाई चौधरी ने कहा, 'उत्तर भारत में अरंडी, जीरे और सरसों की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। इस क्षेत्र में बनासकांठा जिले में ज्यादा नुकसान देखा गया है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों के नजदीक होने की वजह से इस जिले में फसलों पर कीटों का ज्यादा असर देखा गया है। रेगिस्तानी इलाकों से टिड्डे गुजरात में प्रवेश करते हैं।'

सूत्रों का कहना है कि जहां 1990 के दशक के शुरू में हुआ कीटों का हमला कच्छ जिले और इसके आसपास के कुछ इलाकों तक सीमित था वहीं इस बार हुआ हमला ज्यादा भयंकर है। चौधरी ने कहा, 'कीटों के इस हमले को लगभग एक महीना बीत चुका है और किसानों तथा राज्य सरकार द्वारा उठाए गए उपचारात्मक कदम पर्याप्त साबित नहीं हुए हैं।'

गुजरात में टिड्डों का झुंड पाकिस्तान और राजस्थान के रास्ते पश्चिम एशिया से आया है और बनासकांठा में फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा पास के साबरकांठा और मेहसाणा जैसे जिलों में भी कीटों के हमले से नुकसान हुआ है। साबरकांठा, मेहसाणा और पाटन में हालांकि कम नुकसान हुआ है।

गुजरात सरकार के कृषि आंकड़ा निदेशालय के अनुसार, अब तक बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकंठा, अरावली और गांधीनगर जिलों समेत उत्तर गुजरात क्षेत्र में 11 लाख हेक्टेयर का रबी फसल का रकबा दर्ज किया गया है जिसमें 3,40,100 हेक्टेयर में गेहूं की फसल है।

इस सप्ताह के शुरू में, गुजरात के कृषि मंत्री आर सी फलदू ने कहा था कि कीटों के हमले से मूंगफली, अरंडी और कपास जैसी खरीफ फसलें तथा सरसों, जीरा और गेहूं जैसी रबी फसलें प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा, 'ये टिड्डे ओमान से आए हैं और हवा के दबाव की वजह से ये उत्तर गुजरात की ओर मुड़े हैं। हमने किसानों की मदद के लिए कीटनाशकों का छिड़काव शुरू किया है। बनासकंठा में लगभग 87 गांव टिड्डे के हमले से प्रभावित हुए हैं। हम पास के इलाकों में इन्हें पहुंचने से रोकने के सभी एहतियाती उपाय अपना रहे हैं।'

हालांकि टिड्डों की मौजूदगी के बावजूद इस बार कच्छ जिले में फसलों पर नुकसान नहीं देखा गया है। जानकारों का मानना है कि टिड्डों को फसल से दूर रखने के लिए ग्रामीणों द्वारा शोरगुल वाले संगीत बजाने, स्टील प्लेट और ढोल बजाने जैसे पारंपरिक उपायों के बजाय कुछ प्रभावी तरीकों को अपनाए जाने की जरूरत है।

कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क में न हो कटौती

भाषा
नई दिल्ली, 27 दिसंबर

- **सॉल्वेंट एक्स्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने सरकार से कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क को मौजूदा 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत नहीं करने का आग्रह किया**
- **इससे घरेलू तिलहन किसानों को नुकसान होने की आशंका जताई गई**

खाद्य तेल उद्योग के प्रमुख संगठन, सॉल्वेंट एक्स्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन (एसईए) ने आज सरकार से कच्चे पाम तेल (सीपीओ) पर आयात शुल्क को मौजूदा 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत नहीं करने का आग्रह किया है। उसका तर्क है कि इस कदम से घरेलू तिलहन उत्पादकों को नुकसान होगा। एसईए ने सरकार से आसियान समझौते के अनुरूप सीपीओ और रिफाइंड पामोलिन के बीच के शुल्क अंतर को मौजूदा 10 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत तक कम नहीं करने का भी आग्रह किया है। यह समझौता एक जनवरी, 2020 से शुरू होने की संभावना है।

संगठन के बयान के अनुसार ऐसी खबरें हैं कि वनस्पति इंडस्ट्री एसोसिएशन ने सीपीओ आयात शुल्क को घटाकर 30 प्रतिशत करने की मांग की है। इसमें कहा गया है, 'अगर यह मांग सरकार द्वारा स्वीकार कर ली जाती है, तो यह तेल उद्योग के लिए फायदेमंद हुए बिना तिलहन किसानों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा।'

इसमें कहा गया है कि अगले तीन से पांच वर्षों में देश में लगभग पांच करोड़ टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रहे राष्ट्रीय खाद्य तेल का मिशन का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। एसईए ने कहा, 'हमारा सुझाव है कि सीपीओ और रिफाइंड पामोलिन के बीच शुल्कों के बीच के अंतर को कम करने के बजाय इसे 15 प्रतिशत या न्यूनतम 10 फीसदी (जो मौजूदा समय में है) तक बढ़ाया जाए। मौजूदा समय में तिलहन, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से अधिक कीमत पर बिक रहे हैं। यह तिलहन उत्पादन के भविष्य के लिए अच्छा है क्योंकि किसानों को सही मूल्य संकेत मिल रहे हैं।

एसईए ने कहा, 'पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी खाद्य तेल सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्य तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 70 प्रतिशत तक आयात पर निर्भरता बढ़ गई है।' तेल से लाभ न मिलने के कारण किसानों में इसकी खेती को लेकर रुचि की कमी की वजह से तिलहन उत्पादन में ठहराव की स्थिति बनी हुई है। देश में खाद्य तेलों का जो कुल आयात होता है उसमें पाम तेल का हिस्सा 63 प्रतिशत का है। भारत ने विपणन वर्ष 2018-19 (अक्टूबर-नवंबर) में 94.09 लाख टन पाम तेल का आयात किया था।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Dec 27	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,790.5	4.5	1,947.9	-2.5
Copper	6,184.5	8.2	6,502.2	6.0
Nickel	14,290.0	-17.9	15,134.5	-16.2
Lead	1,905.0	-7.9	2,200.1	4.9
Tin	17,250.0	5.7	17,937.2	0.9
Zinc	2,277.0	-2.5	2,578.5	-1.1
Gold ($/ounce)	1,510.9*	0.9	1,690.6	2.2
Silver ($/ounce)	17.8*	1.7	20.2	2.4
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	67.6*	9.6	67.3	7.9
Natural Gas ($/mmBtu)	2.2*	-7.9	2.2	-8.6
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	192.4	13.4	306.1	3.8
Maize	182.6*	1.9	331.8	9.4
Sugar	361.6*	5.9	487.2	-0.7
Palm oil	755.0	45.2	1,184.1	38.8
Rubber	1,605.3*	9.9	1,835.8	3.6
Coffee Robusta	1,326.0*	0.4	1,863.8	-6.1
Cotton	1,521.6	15.4	1,583.5	-5.1

* As on Dec 27, 19 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.4& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel. 3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker

Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	49.0	14919
Oil and Oilseeds	703.7	75851
Spices	1.0	15
Metal(Dec 26)		
Metal- non ferrous	3133.8	48781
Metal- precious	13669.0	398
Oil and gas(Dec 26)		
Gas	2640.4	42066
Oil	10258.2	3019

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	273.8	110736
Grains	281.0	101815
Oil and Oilseeds	1514.6	555105
Others	181.2	71505
Pulses	131.0	42550
Spices	103.8	29205

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Natural Gas (Dec 26)	163.5	4.7
Crude Palm Oil (Dec 31)	801.0	3.4
Cardamom (Jan 15)	3526.4	3.2
Gold Guinea (Dec 31)	31052.0	1.7
Aluminium (Dec 31)	136.5	1.3
Crude Oil (Jan 17)	4403.0	1.1
Zinc (Dec 31)	177.6	0.7
Aluminium Mini (Dec 31)	135.9	0.6
Mentha Oil (Dec 31)	1296.1	0.5
Gold Petal (Dec 31)	3832.0	0.5
Kapas (Apr 30)	1130.5	0.2
Losers (* % Change)		
Nickel (Dec 31)	1048.1	-0.2

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6610.0	4.1
Coriander-Kota (Jan 20)	6553.0	1.6
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Jan 20)	938.6	0.8
Bajra (Jan 20)	2050.0	0.2
CastorSeed New-Disa (Jan 20)	4218.0	0.2
GuarGum 5T-Jodhpur (Jan 20)	7722.0	0.2
Losers (* % Change)		
Chana-Bikaner (Jan 20)	4485.0	-1.5
CottonSeed Oil-Akola (Jan 20)	2213.0	-1.1
Soyabean Indore (Jan 20)	4416.0	-0.9
Guar Seed 10 (Jan 20)	4216.0	-0.4
Jeera Unjha (Jan 20)	16420.0	-0.4
Mustard Seed Rape Oil (Jan 20)	4622.0	-0.4

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Cardamom Vandanmedu (Jan 15)	3526.4	3.7
Cotton-Rajkot (Dec 31)	19210.0	2.2
Silver Micro-Ahemd (Feb 28)	46833.0	1.4
Silver Ahm (Mar 05)	46823.0	1.4
Gold Ahm (Feb 05)	38882.0	0.2
Nickel Mumbai (Dec 31)	1048.1	0.1
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Dec 31)	1296.1	-8.8
Alumini-Mumbai (Dec 31)	135.9	-4.2
Aluminium Mum (Dec 31)	136.5	-3.8
Zinc Mini Mumbai (Dec 31)	177.5	-3.1
Lead Mum (Dec 31)	149.8	-3.1
Copper Mum (Dec 31)	440.6	-3.1

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6610.0	10.2
29 mm Cotton-Rajkot (Jan 20)	18850.0	0.3
Barley Jaipur (Jan 20)	2137.0	0.3
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Jan 20)	7722.0	0.2
Maize-Sangli (Jan 20)	2105.0	0.2
Jeera Unjha (Jan 20)	16420.0	0.1
<B>Discount over spot price<$> (In %)		
Crude Palm Oil Kandl (Dec 31)	779.6	-6.3
Coriander-Kota (Jan 20)	6553.0	-5.0
Soy Bean Indore (Jan 20)	4416.0	-2.8
Paddy-Basmati-Karnal (Jan 20)	3213.0	-1.1
Moong-Merta City (Jan 20)	7116.0	-0.5

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	104......(104)
Aluminium ingots /kg	139......(137)
Brass sheet cutting /kg	328......(325)
Brass utensil scraps/kg	309......(307)
Copper heavy scrap /kg	431......(428)
Copper utensil scraps/kg	405......(405)
Copper wire bar /kg	464......(461)
Lead ingots /kg	157......(157)
Nickel Cathodes /kg	1080......(1080)
Tin slabs /kg	1280......(1285)
Zinc slabs /kg	184......(182)

Source:Bombay Metal Exchange

Cotton	Mumbai
Bengal Deshi /Qtl	10320......(10404)
DCH - 32 /Qtl	11248......(11248)
Jaydhar /Qtl	10095......(10095)
Shankar- 6 /Qtl	11023......(11023)

Source:Cotton Association of India

Oil	Mumbai
Castor FSG /10kg	898......(898)
Castor Comm /10kg	888......(888)
Ricebran oil/10kg	820......(820)
Groundnut oil /10kg	1155......(1140)
Linseed oil /10kg	975......(910)
Karanji /10kg	780......(780)
Palm oil /10kg	830......(817)
Sunflower exp ref /10kg	910......(900)
Sunflower oil exp /10kg	875......(865)
Soyabean ref / 10kg	910......(890)

Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar	Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3362-3592 ......(3282-3592)

Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	
NYSE Crude	61.88......(61.68)
Brent Crude (UK)	67.74......(67.56)
Brent Crude (WTI)	61.68......(61.68)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	2.2(2.29)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	285.63......(269.49)
Naptha spot /Rs/MT	45170......(45170)
LSHS spot/ M.T.	36150......(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950......(33950)

Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold	Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	38788......(38636)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	38944......(38791)
Silver.999/ kg	46320......(46520)

Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18773.60	18792.30
Alumini-Mumbai (M)	1 K	139.75	141.90
Bajra-Delhi (N)	1 Q	2040.00	2055.00
Bajra-Jaipur (N)	1 Q	2046.25	2053.85
Barley Jaipur (N)	1 Q	2128.75	2130.75
Brass-Jamnagar (M)	1 K	320.90	320.90
Cardamom-Vand. (I)	1 K	3467.00	3450.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4320.60	4315.90
Castor Seed-Kadi (N)	X	4250.00	4262.50
Chana Bikaner (N)	1 Q	4462.30	4407.75
Chana Delhi (N)	1 Q	4661.10	4628.70
Chana-Akola (N)	X	4500.00	4500.00
Coriander-Gondal (N)	X	6525.00	6600.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6733.35	6853.75
Coriander-Kota (N)	1 Q	6792.45	6895.15
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	2246.45	2237.75
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	2244.10	2249.70
Cotton-Kadi (N)	1 B	18683.40	18749.10
CPO-Kandla (M)	10 K	773.10	797.00
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	796.70	831.85
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	900.50	900.85
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1548.35	1547.85
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3454.55	3450.55
Gold Ahm (M)	10 G	38641.00	38791.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	31037.00	31158.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	3876.00	3890.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7625.00	7703.15
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	4111.55	4122.75
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	4075.00	4056.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1207.05	1217.90
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	95.85	96.90
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	16950.00	16950.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	16411.10	16395.85
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1053.35	1059.10
Kapas-Rajkot (N)	X	1060.20	1061.55
Lead Mum (M)	1 K	156.20	154.50
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	2048.15	2048.15
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2434.20	2447.50
Maize-Erode (N)	X	2085.00	2084.00
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2255.00	2227.50
Maize-Sangli (N)	X	2096.25	2100.45
Moong-Merta City (N)	1 Q	7088.90	7150.00
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4797.50	4797.25
Nickel Mumbai (M)	1 K	1060.70	1047.50
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3217.00	3220.00
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3200.00	3250.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	350.00	349.60
Pepper-Kochi (N)	1 Q	35316.65	35216.65
Rape mustards-Patan (I)	20 K	831.00	832.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	2075.00	2078.45
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	805.00	845.00
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	922.85	931.40
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	901.35	918.65
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	930.00	935.00
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13100.00	13100.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13125.00	13133.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	46458.00	46192.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4540.00	4545.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4359.15	4400.00
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4545.00	4545.00
Soy Bean-Akola (N)	X	4500.00	4500.00
Soymeal Indore (N)	1 T	37050.00	37275.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	914.50	918.60
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	29620.00	30080.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	30580.00	31200.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	28440.00	28800.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3245.00	3305.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3383.65	3396.00
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3270.65	3270.00
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3519.05	3519.05
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3350.00	3350.00
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3118.75	3102.50
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	6000.00	6000.00
Wheat Delhi (N)	1 Q	2325.85	2327.50
Wheat Kota (N)	1 Q	2175.00	2175.00
Wheat New Indore (N)	1 Q	2250.00	2250.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2131.25	2130.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2230.00	2250.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	4937.25	6101.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	182.45	183.15

* as on Dec 26, 19

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

DAY SESSION

दिवस सत्र (शुक्रवार)

कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Dec 31	19200, 19230, 19190, 19210	289	40	1361
Jan 31	19350, 19530, 19350, 19460	3733	492	11288
Feb 28	19650, 19750, 19650, 19690	145	27	1276
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Jan 20	2236, 2263, 2198, 2213	67500	4433	58450
Feb 20	2260, 2282, 2220, 2236	33590	2374	41180
Mar 20	2284, 2302, 2243, 2255	2160	209	6370
Apr 20	2299, 2318, 2290, 2307	230	23	400
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1133, 1137.5, 1129, 1130.5	232	51	952
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1134.5, 1139, 1127.5, 1129.5	1839	925	4336
Grains				
Bajra NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	2050, 2050, 2050, 2050	10	1	100
Barley Jaipur NCDEX(1 Q)				
Apr 20	1700, 1700, 1700, 1700	100	1	950
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	4238, 4262, 4204, 4216	46585	4874	66225
Feb 20	4282, 4304, 4248, 4260	19380	2196	33340
Mar 20	4330, 4340, 4298, 4334	170	32	200
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	4198, 4270, 4160, 4218	5230	679	26995
Feb 20	4200, 4282, 4180, 4236	2855	389	8945
Mar 20	4218, 4256, 4216, 4236	235	36	6405
Apr 20	4164, 4258, 4164, 4234	160	28	1300
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Dec 31	785.7, 810.3, 770.7, 801	16500	1033	16490
Jan 31	793.6, 817.8, 776.9, 802.8	59430	3811	46710
Feb 28	793.6, 813.1, 778.1, 800.3	9800	744	11700
Mar 31	789, 803.3, 778, 801.7	660	54	690
Mentha Oil MCX(1 K)				
Dec 31	1300, 1300, 1295, 1296.1	12.24	11	15.48
Jan 31	1309.1, 1311.9, 1301, 1307.8	116.28	286	244.8
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Jan 20	4650, 4662, 4611, 4622	16060	1227	20290
Feb 20	4592, 4618, 4572, 4588	1950	119	3760
Apr 20	4529, 4541, 4491, 4522	4140	313	10490
May 20	4530, 4530, 4530, 4530	30	3	530
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Jan 20	939, 950, 924.6, 938.6	40085	4478	42825
Feb 20	939, 948, 925.8, 935.6	31630	3415	48550
Mar 20	927.2, 937.8, 917.6, 926.4	9440	1030	20320
Apr 20	904, 920, 902, 913.4	475	74	1085
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Jan 20	4458, 4480, 4402, 4416	66080	7786	125260
Feb 20	4490, 4504, 4426, 4438	50275	5710	158210
Mar 20	4510, 4522, 4440, 4462	17045	2067	70355
Apr 20	4548, 4552, 4470, 4492	3820	370	9220
May 20	4582, 4582, 4550, 4552	280	9	565
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	7730, 7786, 7652, 7722	13765	1688	39760
Feb 20	7825, 7885, 7758, 7824	9460	957	31570
Mar 20	7882, 7967, 7882, 7900	90	18	175
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	4555, 4555, 4476, 4485	22260	1586	32710
Mar 20	4470, 4488, 4425, 4432	6840	547	9390
Apr 20	4425, 4425, 4415, 4420	40	4	390
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Jan 15	3500, 3555.2, 3489.9, 3526.4	1.2	12	7.7
Feb 14	3351, 3453.5, 3350, 3445.3	1.6	16	6.7
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Jan 20	6483, 6642, 6432, 6553	3210	302	9210
Apr 20	6940, 7205, 6936, 7144	2570	241	6430
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Jan 20	16475, 16590, 16385, 16420	786	236	1965
Mar 20	15900, 16020, 15880, 15940	219	64	771
Apr 20	15605, 15610, 15550, 15600	60	20	189
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Mar 20	6392, 6616, 6374, 6610	4150	666	6580
Apr 20	6308, 6534, 6284, 6518	3070	399	4035

धातु

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Dec 31	137.05, 137.05, 135.1, 136.9	125	18	345
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Dec 31	136.05, 136.25, 136, 136.2	36	7	118
Jan 31	136.85, 137.15, 136.25, 137	2691	1482	5328
Feb 28	137.1, 137.6, 136.9, 137.4	50	46	109
Copper MCX(1 K)				
Dec 31	441, 443, 440.15, 442.7	622.5	216	1505
Jan 31	444.9, 445.7, 444.2, 445.25	8880	3029	12737.5
Feb 28	449.75, 449.75, 448.65, 449.4	65	26	262.5
Lead MCX(1 K)				
Dec 31	150.9, 151.15, 150.9, 150.95	20	4	240
Lead Mini MCX(1 K)				
Dec 31	151, 152.6, 151, 151.45	5	5	19
Jan 31	152.5, 152.75, 152.25, 152.65	2727	1702	5082
Feb 28	153, 153.2, 152.85, 153.1	54	53	48
Nickel MCX(1 K)				
Dec 31	1060, 1060, 1047.6, 1058.1	51	26	117
Jan 31	1034.5, 1034.5, 1027.1, 1029	7186.5	4202	2433
Feb 28	1027.8, 1030, 1024.3, 1028.5	73.5	48	66
Zinc MCX(1 K)				
Dec 31	177.95, 179.8, 177.95, 179.45	165	30	665
Zinc Mini MCX(1 K)				
Dec 31	178.15, 181.7, 178.15, 179.2	157	157	575
Jan 31	179.85, 181.2, 179.85, 180.85	17650	10009	20246
Feb 28	181.1, 181.8, 180.95, 181.45	434	329	735
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	38930, 38980, 38787, 38925	6.1	5172	16.6
Apr 03	39067, 39077, 38887, 39027	0.39	314	5.19
Gold Guinea MCX(8 G)				
Dec 31	31150, 31150, 31009, 31080	0	2	0
Jan 31	31030, 31115, 30981, 31067	0	201	0.01

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Feb 28	31149, 31390, 30984, 31092	0	17	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Jan 03	38805, 38855, 38685, 38792	0.56	4754	0.68
Feb 05	38919, 39010, 38760, 38891	0.53	4234	0.89
Mar 05	38971, 39000, 38795, 38923	0.04	282	0.06
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Dec 31	3890, 3890, 3862, 3873	0	4	0
Jan 31	3892, 3895, 3885, 3892	0	770	0.01
Feb 28	3889, 3890, 3877, 3885	0	80	0
Mar 31	3885, 3885, 3885, 3885	0	1	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	46861, 46929, 46480, 46733	357.42	9708	334.89
May 05	47373, 47409, 46986, 47258	2.43	80	5.94
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	46900, 47006, 46512, 46751	37.53	24899	27.67
Apr 30	47349, 47406, 47000, 47220	2.17	1491	2.93
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	46900, 46948, 46517, 46745	123.28	18481	61.49
Apr 30	47363, 47419, 47004, 47206	1.97	374	2.63

तेल एवं गैस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Jan 28	162.5, 162.7, 156.2, 158.1	83901mb	40049	41886mb
Feb 25	159, 159.2, 153, 155.4	6124mb	3420	9636mb
Mar 26	158, 158.7, 154, 155.4	185mb	133	115mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Jan 17	4394, 4425, 4393, 4421	5686bl	34272	4365bl
Feb 19	4406, 4422, 4400, 4418	141bl	1208	134bl

सायं सत्र (गुरुवार)

कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Dec 31	18990, 19190, 18990, 19160	1012	154	1458
Jan 31	19220, 19470, 19220, 19430	6556	987	10026
Feb 28	19500, 19700, 19500, 19680	493	67	1241
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1115, 1136, 1115, 1134.5	516	88	960
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1116, 1137, 1113, 1136	2220	1215	4022
Oil and Oilseeds				
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Dec 31	753.3, 780.5, 753, 780	15380	991	23610
Jan 31	759.2, 788.6, 759.2, 787.2	46990	2743	42480
Feb 28	764.6, 791.4, 764.5, 789.5	3900	339	10410
Mar 31	768.8, 787, 768.8, 780	130	13	110
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Jan 20	918, 937, 916.4, 936	41440	3966	44025
Feb 20	919.4, 937, 916, 935.2	31945	3193	49655
Mar 20	910.6, 925.6, 909.4, 924.4	16580	1261	17810
Apr 20	905.4, 906, 902.2, 906	1110	128	980

धातु

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Dec 31	135.9, 137.55, 134.6, 136.5	200	33	535
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Dec 31	134.25, 136.45, 134.25, 135.9	860	837	690
Jan 31	136.55, 137.15, 136.05, 137	5412	3848	5512
Feb 28	136.75, 137.55, 136.7, 137.4	97	94	106
Copper MCX(1 K)				
Dec 31	439.6, 441.2, 439.2, 440.6	692.5	238	1807.5
Jan 31	444.15, 446, 444.05, 444.9	14470	5114	11360
Feb 28	448.2, 450.05, 448.15, 449.35	140	54	252.5
Lead MCX(1 K)				
Dec 31	150.15, 151.6, 148.2, 149.75	360	69	355
Lead Mini MCX(1 K)				
Dec 31	150.05, 151.1, 149.75, 150.5	22	22	29
Jan 31	152.1, 153.2, 152.1, 152.35	8689	5250	4416
Feb 28	152.6, 153.5, 152.6, 152.8	54	52	44
Nickel MCX(1 K)				
Dec 31	1046.3, 1069.4, 1040.1, 1048.1	409.5	268	156
Jan 31	1046, 1053.8, 1012, 1034.5	14914.5	8963	1671
Feb 28	1046, 1051, 1014, 1025.1	199.5	128	42
Zinc MCX(1 K)				
Dec 31	176.55, 178.1, 175.35, 177.55	785	140	1075
Zinc Mini MCX(1 K)				
Dec 31	176.55, 178.55, 175.65, 177.45	188	86	1179
Jan 31	179, 180.9, 177.9, 179.6	31571	17484	18975
Feb 28	179.55, 181.7, 178.7, 180.55	846	596	576
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	38635, 38948, 38635, 38882	14.26	11564	15.89
Apr 03	38750, 39040, 38748, 38991	0.86	763	4.9
Gold Guinea MCX(8 G)				
Dec 31	30900, 31289, 30601, 31052	0	13	0
Jan 31	30899, 31039, 30834, 31020	0.01	548	0.01
Feb 28	30880, 31055, 30851, 30973	0	40	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Jan 03	38650, 38816, 38619, 38767	1.65	13181	0.68
Feb 05	38650, 38915, 38650, 38849	0.91	7032	0.76
Mar 05	38645, 38939, 38645, 38897	0.05	442	0.05
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Dec 31	3868, 3871, 3706, 3832	0	47	0
Jan 31	3877, 3892, 3875, 3889	0	1556	0.01
Feb 28	3862, 3886, 3862, 3882	0	174	0
Mar 31	3866, 3875, 3860, 3871	0	13	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	46589, 47232, 46519, 46823	985.5	26368	290.4
May 05	47399, 47688, 47031, 47309	5.19	169	5.49
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	46599, 47250, 46524, 46833	98.95	65143	24.48
Apr 30	47200, 47724, 47000, 47298	5.19	3801	2.82
Jun 30	47880, 48150, 47610, 47956	0.01	10	0.02
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	46575, 47250, 46533, 46837	342.24	50464	50.13
Apr 30	47130, 47713, 47029, 47315	7.13	1196	2.43

तेल एवं गैस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Dec 26	158, 161.7, 157.6, 163.5	86256mb	38327	3099mb
Jan 28	158.8, 163.2, 158.8, 162.7	73221mb	35065	30950mb
Feb 25	156.9, 159.7, 156.9, 159.3	4841mb	2778	8018mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Jan 17	4370, 4414, 4353, 4403	22916bl	135854	2912bl
Feb 19	4365, 4407, 4355, 4398	491bl	4042	107bl

g-grams, k-kilograms, q-quintals, t-tonnes, b-bales,bl-barels,mb-mmBTU,m-Mnd; Quantity & Open interest in tonnes except for crude oil and natural gas; For Gas is '000 mmBTU & for crudeoil in '000 barrel; Market price in ₹.

राजनीति

केंद्र में मजबूत सरकार

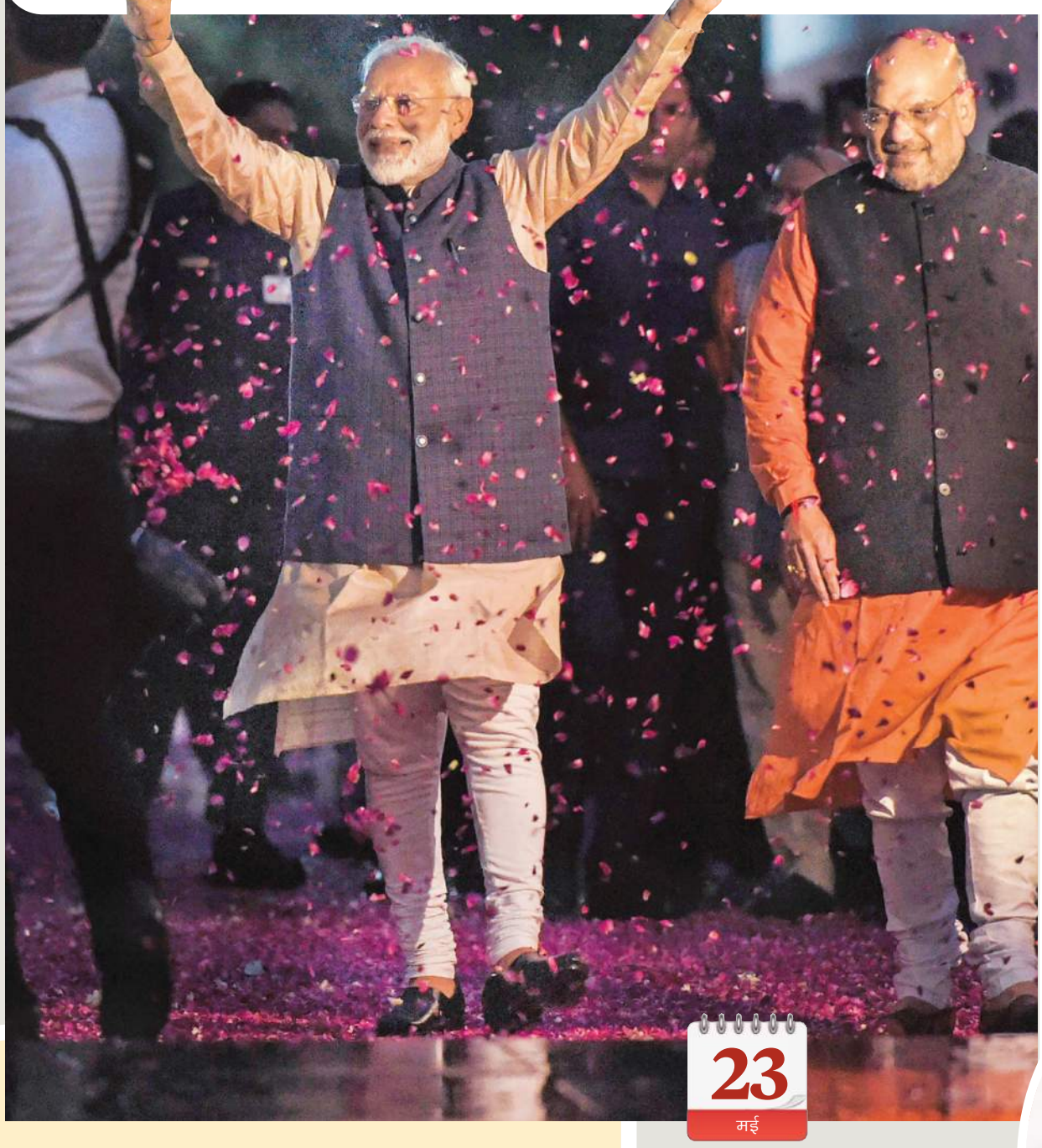

23 मई

बहुमत कम होने के अनुमानों को गलत साबित करते हुए नरेंद्र मोदी की अगुआई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 354 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। मोदी 1971 के बाद ऐसे पहले नेता हैं जिनकी पार्टी ने लगातार दो चुनावों में अपने बलबूते बहुमत हासिल किया है। कांग्रेस की सीटों की संख्या महज 52 रही।

3 जुलाई

राहुल गांधी ने लोक सभा चुनावों में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी मां सोनिया गांधी ने पार्टी द्वारा नया अध्यक्ष तलाशे जाने तक अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। हालांकि अध्यक्ष की खोज अभी जारी ही है।

24 अक्टूबर

हरियाणा में विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या में बड़ी कमी आई। इसके चलते पार्टी ने देवी लाल के पोते द्वारा स्थापित एक स्थानीय पार्टी और सात निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाई।

1 जुलाई

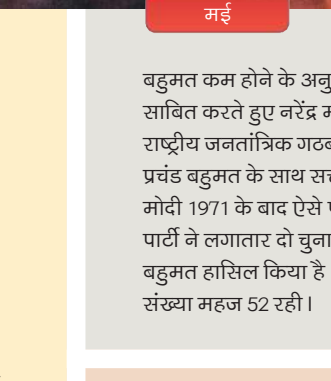

23 दिसंबर

कर्नाटक में 16 विधायकों के इस्तीफा देने और भाजपा में शामिल होनेके बाद राज्य में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार गिर गई। विधानसभा अध्यक्ष ने इस्तीफे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद घूस, ब्लैकमेल, रिसॉर्ट में विधायकों को रखने के आरोपों और सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। सत्तारूढ़ सरकार के विधानसभा में बहुमत साबित न कर पाने पर भाजपा ने सरकार बनाई। दिसंबर में उपचुनाव में बागी विधायकों में से 12 विधायक अपनी सीट जीत गए, जिससे विधानसभा में भाजपा का बहुमत और पुख्ता हो गया है।

नक्सल प्रभावित राज्य झारखंड में पांच चरणों में हुए चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुआई वाले गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की। गठबंधन ने 81 में से 47 सीटों पर जीत दर्ज की। तस्वीर में मुख्यमंत्री (मनोनीत) हेमंत सोरेन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ।

26 फरवरी

भारतीय लड़ाकू विमानों ने कश्मीर में सीमा रेखा पार कर पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी प्रशिक्षण शिविर पर बम गिराए। यह कार्रवाई जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकवादियों के हमले में भारतीय सुरक्षा बलों के जवान शहीद होने के जवाब में की गई। पाकिस्तान ने अगले दिन पलटवार किया। इसमें भारत का एक लड़ाकू विमान गिर गया और विमान के पायलट अभिनंदन वर्धमान (दाएं) को बंदी बना लिया गया। वर्धमान को 60 घंटे बाद रिहा किया गया।

5 अगस्त

संविधान में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को विवादित परिस्थितियों में खत्म कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा जाएगा। राज्य में अब भी बंद जैसे हालात हैं और सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य में बंदी प्रत्यक्षीकरण स्थगित है और राज्य के नेताओं को नजरबंद रखा गया है।

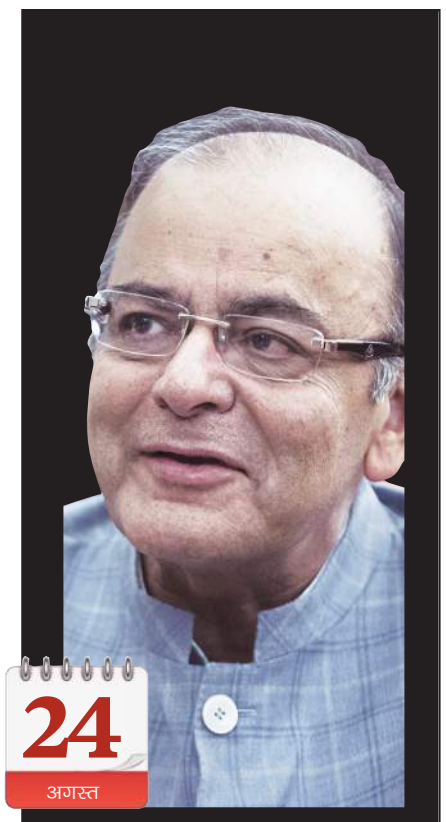

24 अगस्त

नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के प्रभावशाली वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के विश्वासपात्र अरुण जेटली का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया।

31 अक्टूबर

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने। जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तब उनके पूर्व प्रधान सचिव जी सी मुर्मू को जम्मू-कश्मीर का पहला उप-राज्यपाल नियुक्त किया गया। पूर्व रक्षा सचिव आर के माथुर को लद्दाख का पहला उप-राज्यपाल नियुक्त किया गया।

28 नवंबर

महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उसे बहुमत नहीं मिला। इसके नतीजतन पर्दे के पीछे जोड़-तोड़ की राजनीति चली और राकांपा के शरद पवार किंगमेकर साबित हुए। भाजपा का चुनाव पूर्व सहयोगी शिव सेना के साथ समझौता नहीं हो सका। ऐसे में शिव सेना, राकांपा और कांग्रेस के मिलकर सरकार बनाने के आसार थे, जिसमें उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जाना था। इस बीच अचानक भाजपा के देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि फडणवीस ने विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। शिव सेना, राकांपा और कांग्रेस गठबंधन ने सरकार बनाई और शिव सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हैं।